● वर्ष-5
● अंक-261
रायपुर, गुरुवार
18 जून 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› टाउनहॉल में मोदी सरकार के 12 वर्ष ...

हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप जीते थेः भागवत

नईदिल्ली। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की स्पष्ट जीत का दावा करते हुए प्रचलित ऐतिहासिक विवरणों को चुनौती दी। उन्होंने मुगल इतिहासकारों के हवाले से कहा कि पहले हमले के बाद मुगल सेना कई मील पीछे हटी थी, जिससे जीत का मौजूदा नैरेटिव गलत साबित होता है। भागवत ने भारतीय इतिहास में हमलावरों को महिमामंडित करने वाले गलत नैरेटिव की आलोचना की।

उदयपुर में महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके प्रमुख मोहन भागवत ने इतिहास के प्रचलित विवरणों को चुनौती देते हुए कहा कि हल्दीघाटी की लड़ाई में राजपूत राजा की स्पष्ट जीत हुई थी। भागवत ने भारतीय इतिहास में मौजूद गलत नैरेटिव की आलोचना की।

उन्होंने कहा कि सदियों से यहाँ के मूल शासकों के बजाय हमलावरों को महिमामंडित किया गया है। उन्होंने कहा कि हल्दीघाटी की लड़ाई में जीत महाराणा प्रताप और भारत की तरफ से लड़ने वालों को मिली थी ङ्क यह बिल्कुल साफ है। ऐतिहासिक बहस एकतरफा थी, लेकिन तथ्य उस नैरेटिव को गलत साबित करते हैं। इस आम राय पर बात करते हुए कि 1576 की लड़ाई अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य की रणनीतिक जीत के तौर पर खत्म हुई, भागवत ने मुगल इतिहासकारों के बयानों का ज़िक्र किया। उन्होंने बताया कि इतिहासकारों ने खुद माना था कि पहले हमले के बाद उनकी सेना को कई मील पीछे हटना पड़ा था। उन्होंने कहा कि अगर हम खुद मुगल इतिहासकारों की लिखी बातों पर गौर करें, तो वे बताते हैं कि पहले ही हमले में उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ी और छह-सात मील पीछे हटना पड़ा। तो फिर जीत किसकी हुई? उस दौर में भी ऐसे इतिहासकार थे जो गलत नैरेटिव या कहानियाँ गढ़ते थे।

महाराणा प्रताप की विरासत को आज के समय से जोड़ते हुए भागवत ने कहा कि आज महाराणा प्रताप की जयंती है। कल इस लड़ाई को चार सौ पचास साल पूरे हुए। हल्दीघाटी की लड़ाई को जीत क्यों माना जाता है? इसलिए क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था; आज ही आने वाले कल के नतीजों की वजह बनता है। हमें यह बात समझनी चाहिए।

भारतीय सभ्यता और दुनिया पर उसके असर के बारे में बात करते हुए, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत का ऐतिहासिक प्रभाव जीत हासिल करने के बजाय सेवा और ज्ञान के ज़रिए फैला। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि कोई व्यक्ति जो भी रास्ता चुनता है, वह सही है; यह पूरी तरह से उन पर, उनकी भावनाओं और ईश्वर या शुभ समय के बारे में उनकी सोच पर निर्भर करता है। इसी वजह से हमने सभी का स्वागत किया, सभी का पालन-पोषण और सुरक्षा की, और सभी के साथ ज्ञान साझा किया।

फ्रांस में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात

मोदी एक बहुत ही कुशल वार्ताकारः ट्रंप

नईदिल्ली। फ्रांस में चल रहे जी 7 शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि फ्रांस में हमारी कुछ बेहतरीन बैठकें हुईं, खासतौर पर भारत के प्रधानमंत्री के साथ हमारी कुछ बहुत अच्छी बातचीत हुई।

पीएम मोदी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा , वे एक बहुत ही कुशल वार्ताकार हैं। आप इस आदमी को देखिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। वे देखने में बेहद खूबसूरत हैं। वे इतने अच्छे दिखते हैं मानो कोई फरिश्ते हों लेकिन असल में, वे जितने सख्त हैं, उतने ही खतरनाक भी। वे दिखने में इतने अच्छे हैं कि लोग उनसे चौंक जाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लोग कहते

हैं कि वे बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने कहा कि वे बहुत सख्त हैं। वे एक कुशल व्यापारी हैं और वे भारतीय जनता से प्यार करते हैं लेकिन वे अमेरिका से भी प्यार करते हैं। ह्यूस्टन में हमारा 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हम भविष्य में कभी भारत ज़रूर जाएँगे।

भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर उन पर हमला होता है तो हम उनकी मदद के लिए वहां मौजूद रहेंगे। अगर उन पर हमला होता है और पीएम मोदी नेता हैं तो हम मदद के लिए वहां मौजूद रहेंगे।

ट्रंप ने कहा, यह जी7 शिखर सम्मेलन है। जी 2 आगामी है और फिर जी 20 आगामी है। विशेष रूप से, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारी कुछ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हम व्यापार समझौते कर रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच बहुत कुछ हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। हमें 19.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का निवेश प्राप्त हो रहा है और हम कारखाने बना रहे हैं, हम सब कुछ बना रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत कुछ निर्माण कर रहे हैं। वे अमेरिका में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं इसलिए हम उनके काम की सराहना करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि वे लंबे समय से मेरे मित्र हैं और हमारे हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं और आपके साथ होना बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि दोनों देश व्यापार समझौतों पर काम कर रहे हैं।

भारत पर हमला हुआ तो हम साथ खड़े होंगे...

फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन में आयोजित जी7 समिट 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई. पिछले 16 महीनों में दोनों नेताओं की ये पहली आमने-सामने की बैठक थी. ऐसे समय में ये मुलाकात हुई जब भारत-अमेरिका संबंध ट्रेड, टैरिफ और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर नई दिशा तलाश रहे हैं. वर्किंग लंच के दौरान ट्रंप ने मोदी की खुलकर तारीफ की, जबकि मोदी ने वैश्विक भरोसे, समुद्री सुरक्षा और भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाय।

15 जुलाई से लागू होगा भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता

नई दिल्ली। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) 15 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा। दोनों देशों ने बुधवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। इस समझौते के लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के कारोबारियों को बड़े स्तर पर शुल्क (टैरिफ) में राहत मिलेगी और दोनों देशों के बीच व्यापार को नई गति मिलेगी। यह समझौता हस्ताक्षर होने के बाद सबसे तेजी से लागू होने वाले व्यापार समझौतों में से एक माना जा रहा है। अब कारोबारियों के पास इसकी तैयारियां पूरी करने के लिए 28 दिन का समय है।

ब्रिटेन सरकार के अनुसार, इस समझौते से लंबे समय में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था (जीडीपी) में लगभग 4.8 अरब पाउंड की बढ़ोतरी होगी।

वहीं, वास्तविक मजदूरी में 2.2 अरब पाउंड का इजाफा होने का अनुमान है। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार हर साल 25.5 अरब पाउंड तक बढ़ सकता है।

इस समझौते के तहत कई ब्रिटिश उत्पादों पर भारत में लगने वाले आयात शुल्क में बड़ी कटौती की जाएगी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में शुल्क 100त्न से घटाकर 10% किया जाएगा, हालांकि यह निर्धारित कोटा के तहत होगा।कॉस्मेटिक उत्पादों पर लगने वाला 22% तक का शुल्क समाप्त किया जाएगा या चरणबद्ध तरीके से खत्म होगा।

उत्पादों को भी मिलेगा फायदा

ब्रिटेन भी भारत से आने वाले कई उत्पादों पर शुल्क कम करेगा। इसमें कपड़े, जूते-चप्पल और कुछ खाद्य उत्पाद शामिल हैं। इससे भारतीय निर्यातकों को ब्रिटिश बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। ब्रिटेन का कहना है कि भारतीय सामान के आयात पर लागत कम होने से वहां के उपभोक्ताओं को सस्ते उत्पाद और अधिक विकल्प मिल सकेंगे। समझौते के साथ ही यूके-इंडिया डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट भी लागू होगा। इसके तहत काम के लिए भारत जाने वाले ब्रिटिश नागरिकों और ब्रिटेन जाने वाले भारतीय पेशेवरों को सामाजिक सुरक्षा योगदान को लेकर राहत मिलेगी। अब ब्रिटेन से भारत आने वाले कर्मचारी 36 महीने की बजाय 60 महीने तक केवल अपने देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में योगदान दे सकेंगे।

मुख्यमंत्री नगर पंचायत शिवनंदनपुर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज अपने सूरजपुर प्रवास के दौरान नवनिर्मित नगर पंचायत शिवनंदनपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष श्री रितेश जायसवाल सहित सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए जनसेवा और विकास के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया।इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने नगर पंचायत शिवनंदनपुर के वार्ड क्रमांक 06 में सुसज्जित मंगल भवन निर्माण की घोषणा कर क्षेत्रवासियों को महत्वपूर्ण सौगात दी। मुख्यमंत्री की घोषणा पर उपस्थित नागरिकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनका आभार जताया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिवनंदनपुर को नगर पंचायत का दर्जा मिलना क्षेत्र की वर्षों पुरानी आकांक्षा की पूर्ति है। इससे क्षेत्र में सुनियोजित नगरीय विकास का मार्ग प्रशस्त होगा तथा नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ अपने प्रतिनिधियों का चयन किया है, उस विश्वास पर खरा उतरना अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

प्रमुख समाचार

राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी 20 जून को ओडिशा दौरे पर

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को ओडिशा के मयूरभंज जिले में संताली समुदाय के पवित्र स्थल गोसानी में पूजा-अर्चना करेंगे। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मुर्मू के ससुराल वालों के पैतृक गांव पहाड़पुर का दौरा करेंगे। इसके साथ

ही राष्ट्रपति के 68वें जन्मदिन पर पारंपरिक संताली अनुष्ठानों में भाग लेंगे। उस दिन दोपहर के आसपास मोदी के पहाड़पुर के हेलीपैड पर उतरने और फिर गोसानी जाने की उम्मीद है, जहां वे और मुर्मू प्रार्थना करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले, 19 जून को राष्ट्रपति के पास के रायरांगपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित और संताली भाषा की शोधकर्ता दमयंती बेशरा के अनुसार, गोसानी एक पूजनीय ग्राम देवता और पूर्वजों की आत्माओं तथा सामुदायिक नेताओं के आध्यात्मिक संरक्षकों का स्थान है। उन्होंने कहा, संताली लोग नए उद्यम शुरू करने और लंबी यात्राओं से सुरक्षित लौटने की खुशी में गोसानी में

राहुल गांधी ने टेलीग्राम एप प्रतिबंध पर सरकार को घेरा

नईदिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने टेलीग्राम एप पर अस्थायी प्रतिबंध मामले में सरकार को घेरा है। भाजपा ने पलटवार किया है। राहुल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मोदी सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम पर प्रतिबंध को एक नए तरीके के रूप

में पेश किया है। हालांकि, आलोचकों का मानना है कि यह समस्या की जड़ पर वार करने के बजाय पीड़ित के दरवाजे पर ताला लगाने जैसा है। लाखों छात्र वर्षों से टेलीग्राम का उपयोग नोट्स, टेस्ट सीरीज और पढ़ाई के लिए करते रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, यह सुविधा छीनना पेपर लीक का समाधान कैसे हो सकता है, यह सवाल उठाया गया है। यह तरीका भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, जिसे देश के छात्र और पेपर लीक माफिया दोनों जानते हैं। परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी ली जाएगी और जेबें कैंची से काटी जाएंगी। प्रश्नपत्र वायुसेना के माध्यम से भेजे जाएंगे, नाटकीयता की कोई कमी नहीं होगी। लेख में कहा गया है कि बीमारी की जड़ पर कोई प्रहार नहीं किया जा रहा है।

ओपी राजभर का बड़ा दावा सपा में हो सकती है बड़ी टूट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जल्द ही एक बहुत बड़ी टूट देखने को मिल

सकती है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि अब अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि जब कोई बिकने के लिए तैयार होता है, तभी उसे खरीदा जाता है। राजभर ने सपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर सीधा निशाना साधते हुए दावा किया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक गुप्त पत्र भेजा है, जिसमें कुछ नाम देकर उन्हें अपने साथ ले जाने और खुद को सुरक्षित रखने की बात कही गई है। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि सीबीआई ने अवैध खनन मामले में उनका नाम दर्ज किया है। और सवाल उठाया कि गोमती रिवरफ्रंट घोटाले में अब तक कोई जेल क्यों नहीं गया।

पंजाब सीएम भगवंत मान पर गहराया नैतिक संकट

चंडीगढ़। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने बुधवार को कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। यह बात सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था, श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा एक विवादित वीडियो पर दिए गए

फैसले के बाद कही गई है; इस वीडियो में कथित तौर पर सिख धर्म की सम्मानित हस्तियों और भावनाओं का अनादर किया गया है। चुघ ने याद दिलाया कि जब कई महीने पहले यह वीडियो पहली बार सामने आया था, तो मान ने इसे बनावटी बताते हुए खारिज कर दिया था और दावा किया था कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाया गया है। वह अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के सामने पेश हुए और चुनौती दी कि किसी सक्षम एजेंसी से इस वीडियो की जांच कराई जाए, क्योंकि यह नकली है। चुघ के अनुसार, इस तरह मान ने अपनी विश्वसनीयता को उस जांच के नतीजे पर टिका दिया था। 15 जून को पंथिक हस्तियों, संस्थाओं और सिख संगठनों के साथ हुई बातचीत में सारी सच्चाई सामने आ गई।

टीएमसी के पूर्व मंत्री उदयन गुहा कूचबिहार से गिरफ्तार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता उदयन गुहा को बुधवार को पुलिस ने उत्तरी बंगाल के कूचबिहार ज़िले से गिरफ़्तार किया। पुलिस ने अभी तक गिरफ़्तारी की वजह नहीं बताई है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल सितंबर में बंगाल विधानसभा में विपक्ष के तत्कालीन नेता सुवेंदु

अधिकारी ने राज्य पुलिस पर आरोप लगाया था कि वे उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा को उस मामले में बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पिछले महीने कूचबिहार जिले में उनके काफिले पर कथित हमले से जुड़ा था। अपने आरोप के समर्थन में अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच द्वारा सोमवार को जारी एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक को 10 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर (जिसमें उन्होंने उदयन गुहा को मुख्य आरोपी बताया था) और पुलिस द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज की गई एफआईआर एक ही तरह की थीं। या क्या अधिकारी की शिकायत किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है।

आकांक्षाओं का गणित

भारत में रोजगार का सवाल अब स्थिरता पर क्यों निर्भर है

डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन

जब 1954 में सर आर्थर लुईस ने गरीब अर्थव्यवस्थाओं के अमीर बनने की परिघटना को समझाने का काम शुरू किया, तो उन्होंने विकास की मुख्य प्रक्रिया को पूंजीके संचयके रूप में नहीं बल्कि कामगारों के जीवन-निर्वाह वाली खेती से हटकर अधिक कमाई वाले उद्योगों एवं सेवा क्षेत्रों की ओर मुड़ने के तौर पर पहचाना। उनका यह अनुमान बिल्कुल ही सही था कि यही बदलाव देर से औद्योगीकरण करने वाले हर देश का भविष्य तय करेगा।आज भारत ठीक इसी मोड़ पर खड़ा हैऔर नीति-निर्माताओं के सामने सवाल पर्याप्त नौकरियां उपलब्ध कराने भर का नहीं है। बल्कि, उनके सामने इससे भीअधिक अहम सवाल यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी नौकरियां पैदा करने की स्थिति में है या नहींजो पर्याप्त तादाद में हों, औपचारिक हों और एक युवा कामगार को जीवन भर बढ़ती उत्पादकता एवं सुरक्षा दे सकने लायक टिकाऊ हों।

इस जिम्मेदारी के भार को काफी सटीकता से बताया जा सकता है।'आर्थिक समीक्षा 2023-24'ने 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 'और आबादी से जुड़े अनुमानों के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि इस दशक की बाकी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था को हर वर्ष लगभग 78.5 लाख गैर-कृषि नौकरियां सृजितकरनी होंगी। यह आंकड़ा दो बढ़ते दबावों का नतीजा है- पहला, कामकाज के क्षेत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ने के साथ श्रमशक्ति में हो रही लगातार बढ़ोतरी; और दूसरा, संरचनात्मक बदलाव के कारण खेती से बाहर आने वालेकामगार।रोजगार में खेती की हिस्सेदारी अभी भी लगभग 46 प्रतिशत है। वर्ष 2047 तकइस हिस्सेदारी के घटकर एक-चौथाई तक आ जाने की संभावना है।

जुलाई 2025 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई और उसके अगले महीने से शुरू हुई 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना'उस अंतर को पाटने की अब तक की सबसे सोची-समझी कोशिश है। इस योजना के तहत, जुलाई 2027 तक की दो वर्षों की अवधि में 3.5 करोड़ से अधिक औपचारिक नौकरियां सृजित करने हेतु'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 'के जरिए 99,446 करोड़ रुपये लगाए जा रहे हैं।ईपीएफओमें पंजीकृत किसी

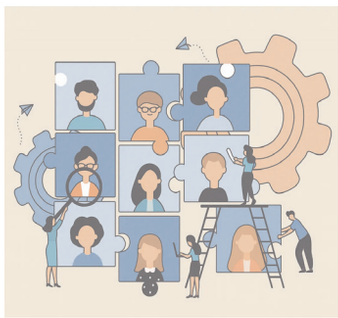

कंपनी में पहली बार शामिल होने वाला और महीने में एक लाख रुपये से कम कमाने वाला कामगार, दो किस्तों में कुल 15,000 रुपये तक पाने का हकदार बन जाता है। दूसरी किस्त वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रमकरने पर और बचत के तौर पर मिलती है। वहीं, निर्धारित आधार-रेखा से अधिक लोगों को नौकरी पर रखने वाले नियोक्ताओं को हर नए कामगार के लिए महीने में 3,000 रुपये तक मिलते हैं। ये शर्तें कुछ इस तरह तय की गई हैं कि छोटी कंपनियां भी इसके दायरे से बाहर हो जाने के बजाय इसमें शामिल हो सकें।

यह योजना भर्तीसंबंधी सब्सिडी वाले आम व निराशाजनक तरीकों से इसलिए अलग और बेहतर है क्योंकि इसमें पहला लाभ मिलने से पहले छह महीने तक लगातार नौकरी करना आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार काम करने वाले को नौकरी पर रखने का लाभ तभी मिलता है जब वह कर्मचारी काम में कुशल बन जाए और टिका रहे। यह शर्त शुरुआती भर्ती को एक पक्की प्रतिबद्धता में बदल देती है, जिससे नियोक्ता को प्रशिक्षण की लागत वसूलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है और कर्मचारी को भी उतने महीने मिल जाते हैं जिनमें वह असली हुनर सीख सके और भरोसेमंद रिकॉर्ड बना सके। इस तरह, यह योजनाकेवल नौकरी देने के लिए नहींबल्कि कर्मचारी को बनाए रखने की अपेक्षाकृत अधिककठिन प्रक्रिया के लिए पुरस्कृत करती हैऔर इसके बाद कर्मचारी के पास रोजगार क्षमता एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्डहोता है जिसका वह कहीं भी सदुपयोग कर सकता है।

इस योजना का सबसे अधिक झुकाव मैन्यूफैक्चरिंग की ओर है, जहां नियोक्ता को मिलने वाला प्रोत्साहन दो वर्ष के बजाय चार वर्ष तक मिलता है। समय-सीमा को दोगुनी करने का यहनिर्णयऔद्योगिक क्षमता तैयार होने में लगने वाले अधिक समय को ध्यान में रखकर लिया गया है। साथ ही, इससे निर्माता समय से पहले स्वचालित व्यवस्था लाकर कामगारों को हटाने के बजाय श्रमशक्ति बढ़ाने की ओर प्रेरित होते हैं। अहम बात यह है कि सरकार ने इसे देश कोवैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग केन्द्रबनाने के लक्ष्य को हासिल करने की दृष्टि से जरूरी माना है। ईपीएफओके जरिए, हर नए कामगार को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा का पहली बार अहसास होता है। अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले बहुत कम कामगारों को यह सुरक्षा मिल पाती है। इस योजना के शुरुआती नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे हैं। इसकेशुरू होने के बाद से लगभग 60 लाख नए कर्मचारी नामांकित हुए हैं।इनमें से अधिकतर 30 वर्ष से कम आयु के हैं और 18 लाख से अधिक महिलाएं हैं।

कांकेर किसान मेले में स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल

कांकेर। जैविक खेती मिशन योजना के तहत जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया गया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों का सम्मान भी किया गय।।

जिला मुख्यालय में आयोजित किसान मेले में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आह्वान पर प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो रही है, इसलिए किसानों को धीरे-धीरे जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहिए।स्वास्थ्य मंत्री ने किसानों को फसल विविधीकरण के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि जो किसान धान की जगह मक्का, दलहन, तिलहन अथवा अन्य फसलों का उत्पादन करेंगे, उन्हें राज्य सरकार की ओर से प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि और महतारी वंदन योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

किसान मेले में स्वास्थ्य मंत्री ने पांच किसानों को कांकेर की पारंपरिक और सुगंधित धान किस्म 'चिरईनखी' के बीच भी बांटे। वहीं जैविक खेती, दलहन-तिलहन उत्पादन, जल संरक्षण और पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दस प्रगतिशील किसानों को शॉल और नारियल का पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों ने भी जैविक खेती के लाभों और तकनीकों की जानकारी किसानों को दी।

स्वास्थ्य मंत्री ने जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि जल्द ही कांकेर में एमआरआई सुविधा शुरू की जाएगी। साथ ही मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित इस किसान मेले में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

आरक्षित भूमि पर खेल मैदान बनाने का विरोध

धमतरी। धमतरी जिले के ग्राम बारना में कुम्हार समाज के लिए आरक्षित भूमि को यथावत बनाए रखने की मांग उठी है। कुम्हार समाज के प्रतिनिधियों ने इस बारे में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके पारंपरिक व्यवसाय के लिए आरक्षित भूमि को खेल मैदान के रूप में उपयोग करने की तैयारी की जा रही है, जिससे समाज के लोगों के रोजगार और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुम्हार समाज ने सौंपे गए आवेदन में बताया कि साल 2008 में ग्राम बारना में कुम्हार समाज के पारंपरिक व्यवसाय को बढ़ावा देने और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खसरा नंबर 514/2, रकबा 1।84 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई थी। इसी प्रकार खसरा नंबर 514/3, रकबा 2 हेक्टेयर भूमि को खेल मैदान के लिए आरक्षित किया गया था।समाज का कहना है कि दोनों भूमियों का उद्देश्य अलग-अलग निर्धारित किया गया है, इसलिए आरक्षित भूमि के मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत एवं कुछ ग्रामीणों ने खसरा नंबर 514/2 की भूमि पर खेल मैदान विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

कुम्हार समाज का कहना है कि उक्त भूमि उनके पारंपरिक व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से मिट्टी सहित अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध होते हैं। यदि इस भूमि का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया जाता है तो समाज के लोगों को भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

कुम्हार समाज वर्षों से मिट्टी के बर्तन और अन्य पारंपरिक वस्तुओं का निर्माण करता आ रहा है। यह केवल रोजगार का साधन ही नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में आरक्षित भूमि को सुरक्षित रखना आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस परंपरा को आगे बढ़ा सकें।

गौ सेवा आयोग अध्यक्ष के साथ अभद्र व्यवहार, भेजा जेल

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त विश्वेश्वर पटेल की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। कबीरधाम शहर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में नशे में धुत युवकों ने उनकी कार को रोककर जमकर हंगामा किया। घटना उस समय हुई जब आयोग अध्यक्ष विश्वेश्वर पटेल जिला मुख्यालय से अपने गृह ग्राम रोहरा लौट रहे थे। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में दो युवक बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक पीछे से विश्वेश्वर पटेल के वाहन से टकरा गई।हादसे के बाद युवकों ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय वाहन को रोक लिया और नशे की हालत में गाली-गलौच शुरू कर दी। आरोप है कि दोनों युवकों ने वाहन में सवार लोगों को धमकाया और हमला करने की नीयत से पत्थर भी उठा लिए।घटना से कुछ देर के लिए मौके पर तनाव की स्थिति बन गई।

एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। बाद में न्यायालय में पेश करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।

ट्रेडिंग के चक्कर में युवाओं को हो रहा नुकसान

कोरबा में फाइनेंशियल कोच जसमीत सिंह छाबड़ा ने दिए इनवेस्टमेंट में टिप्स,

कोरबा। फाइनेंस मैनेजमेंट और सिक्योरिटी को लेकर शहर के टीपी नगर स्थित प्रेस क्लब तिलक भवन में फाइनेंशियल कोच जसमीत सिंह छाबड़ा ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने वित्तीय सुरक्षा, निवेश जागरूकता और पैरामिलिट्री जवानों के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी साझा की। साथ ही बताया कि कैसे युवा फाइनेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं।

निवेश और जोखिम पर बात करते हुए जसमीत ने कहा कि लोगों को अपनी उम्र, आय और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर वित्तीय योजना बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के युवा तेजी से मुनाफा कमाने के लिए ट्रेडिंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 100 में से 95 लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है।जसमीत सिंह छाबड़ा को टॉपनॉच फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2026 के सरदार पटेल एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें दिल्ली में प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि वे पिछले 22 वर्षों से बीएफएसआई (बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस) क्षेत्र से जुड़े हैं और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। जसमीत लंबे समय से निवेश, बचत, धन प्रबंधन और वित्तीय शिक्षा से जुड़ी उपयोगी जानकारी लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। उनके अनुसार, उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म छाबड़ा फाइनेंस राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका है। उन्होंने बताया कि उन्हें केंद्र सरकार की ओर से दो बार सम्मानित किया जा चुका है और हाल ही में उन्ह मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल कोच का अवॉर्ड भी मिला है। जसमीत ने कहा कि उनकी संस्था एक गैर-सरकारी संगठन की तरह काम करती है, जिसका सरकारी विभागों के साथ समन्वय है। संस्था विशेष रूप से पैरामिलिट्री बलों और भारतीय सेना के जवानों के लिए कार्य करती है। उन्होंने बताया कि हाल ही में बस्तर क्षेत्र में नक्सली हमलों में शहीद हुए चार जवानों के परिवारों को संस्था के माध्यम से 25 से 30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

जसमीत ने दिए ये वित्तीय सुझाव

सबसे पहले जीवन बीमा कराएं। हेल्थ इंश्योरेंस लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करें। आपातकालीन जरूरतों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) रखें। नियमित बचत की आदत विकसित करें। लंबी अवधि के लिए म्यूचुअल फंड और एसआईपी में निवेश करें। जोखिम को समझकर ही निवेश करें। अच्छे अंतरराष्ट्रीय फंड्स में सोच-समझकर निवेश किया जा सकता है। सरदार पटेल एकता पुरस्कार 2026 से सम्मानित

200 रुपए के बिल को लेकर किया हंगामा

बिलासपुर। शहर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब अस्पताल भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा स्थित न्यू जनता अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे दो युवकों ने मात्र 200 रुपये के बिल को लेकर देर रात जमकर हंगामा किया। आरोप है कि दोनों युवकों ने अस्पताल कर्मचारियों को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और अस्पताल के मुख्य गेट पर पत्थर मारकर उसे क्षतिग्रस्त कर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार घटना 16 जून की देर रात की है तिफरा स्थित न्यू जनता अस्पताल में देर रात आदित्य बंसोड और युवराज नाम के युवक इलाज कराने पहुंचे। इलाज के बाद बिल भुगतान को लेकर अस्पताल कर्मचारियों से विवाद हुआ। जब कर्मचारियों ने बिल चुकाने को कहा तो दोनों आक्रोशित हो गए। कर्मचारियों के मुताबिक, छोटी चोट होने के कारण बीना ओपीडी शुल्क लिये मात्र ड्रेसिंग चार्ज का 200 रुपए मांगा गया लेकिन इस पर भी युवक गाली-गलौज करने लगे। इस बीच एक युवक ने अपने कमर के पास रखा धारदार बड़ा चाकू निकाला और कर्मचारियों को धमकाते हुए जान से मारने की धमकी दी। हंगामा करने के बाद दोनों आरोपी अस्पताल से बाहर भाग निकले और जाते-जाते अस्पताल के गेट पर पत्थर मारकर उसे तोड़ दिया। जिससे कर्मचारियों के हाथ में चोटे भी आई है। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। वहीं घटना से अस्पताल स्टाफ और मरीजों में डर का माहौल बना हुआ है। अस्पताल कर्मचारी की शिकायत पर सिरगिट्टी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

पाररास रेलवे फाटक रात 9 बजे से सुबह 8 बजे तक रहेगा बंद

बालोद। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बालोद-कुसुमकसा स्टेशन के बीच स्थित पाररास रेलवे फाटक आज रात से बंद रहेगा। रेलवे ट्रैक की जरूरी मरम्मत और मेंटेनेंस कार्य के चलते इस मार्ग पर सड़क यातायात को पूरी तरह से रोका जा रहा है। रेल प्रशासन द्वारा यह यह काम आज रात 9:00 बजे से गुरुवार सुबह 8:00 बजे तक करीब 11 घंटे तक युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। फाटक बंद रहने के दौरान आम जनता और वाहन चालकों की सुविधा के लिए रूट को डायवर्ट किया गया है। रेलवे ने अपील की है कि लोग इस दौरान पाररास रेलवे फाटक की जगह पाररास अंडरब्रिज या बाईपास मार्ग का उपयोग करें, चूंकि काम रात के समय होगा, इसलिए बाहरी या नए वाहन चालकों को रास्ता ढूंढने में परेशानी हो सकती है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने पहले से तैयारी रखने को कहा है। वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ) बालोद द्वारा इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक (स्क) को पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है।पत्र में मांग की गई है कि आम जनता को इस बदलाव की जानकारी देने और वाहनों को व्यवस्थित ढंग से संभालने के लिए मौके पर विभागीय सुरक्षा दल और पुलिस बल की व्यवस्था की जाए। एएसपी मोनिका ठाकुर ने बताया कि रेलवे से प्राप्त पत्र के आधार पर व्यवस्था बनाई जा रही है। रूट डायवर्ट किया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बीएसपी स्क्रैप चोरी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

दुर्ग। भिलाई स्टील प्लांट स्क्रैप चोरी के बहुचर्चित मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी संजय सिंह को उत्तरप्रदेश के देवरिया से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को मंगलवार को दुर्ग लाया गया। वहीं मामले में संलिप्त पाए गए एक अन्य आरोपी पिंटू उर्फ उपेंद्र ओझा को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर सात दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल 26 मई को ग्राम अकलोरडीह खदान पारा स्थित एके ट्रेडर्स, प्लॉट नंबर 18 ए/05, एचआईए हथखोज भिलाई में जांच के दौरान बड़े पैमाने पर बीएसपी से चोरी किए गए स्क्रैप का खुलासा हुआ था। यहां एक खंडेलवाल के नाम पर बीएसपी में फ्लाईएश डस्ट उठाने का टेंडर लिया गया था, जिसमें पार्टनर संजय सिंह ने यह पूरा खेल शुरू किया था। चोरी की घटना के बाद बीएसपी महाप्रबंधक (ब्लास्ट फर्नेस) ने संजय सिंह, मो. सलीम और चिन्तानंद साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था।

दिनदहाड़े इंजीनियर से लूट सीसीटिवी में कैद हुई वारदात

सरगुजा। अंबिकापुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां दिनदहाड़े इंजीनियर से लूटपाट कर आरोपी फरार हो गए। इस वारदात को अंबिकापुर के प्रतापपुर नाका स्थित कुशवाहा चौक पर अंजाम दिया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक केदारपुर कुशवाहा चौक निवासी भगवान कुशवाहा, लोकेश्वर कुशवाहा, आनंद कुशवाहा, सूर्या कुशवाहा ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इंजीनियर से लैपटॉप, कैमरा, स्टैंड लूटकर आरोपी फरार हो गए। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। डेयरी फार्म रोड निवासी अमर कुशवाहा (29) ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि उसके मामा रामनाथ कुशवाहा के नाम पर केदारपुर स्थित कुशवाहा चौक के पास प्लॉट है, जहां मकान निर्माण की तैयारी चल रही थी।

लोरमी वन परिक्षेत्र में तेंदुओं में खूनी संघर्ष में एक की मौत

लोरमी। मुंगेली वनमंडल के लोरमी वन परिक्षेत्र अंतर्गत में दो तेंदुओं के बीच खूनी संघर्ष में एक तेंदुए की मौत हो गई है। वहीं दूसरा तेंदुआ घायल अवस्था में है। घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। शुरूआती जांच में क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर संघर्ष होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कक्ष क्रमांक 1529 पीएफ के सामान्य वनक्षेत्र में बुधवार शाम करीब 7 बजे कंचनपुर बेरियर के चौकीदार ने तेंदुए का शव देखा। इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई। सूचना मिलने के बाद वन अमला मौके पर पहुंचा और रातभर शव की निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था की गई। बताया जा रहा है कि घायल तेंदुआ जंगल की ओर चला गया है। देर रात तक खोजबीन के बावजूद वह अबतक विभाग की नजर में नहीं आया है। ग्रामीणों ने बताया कि घटना से कंचनपुर क्षेत्र में दो तेंदुओं के आपस में लड़ने जैसी तेज आवाजें सुनाई दी थीं। ग्रामीणों की आशंका है कि आपसी संघर्ष में नर तेंदुए की मौत हुई हो सकती है।

प्रसूता और शिशु की मौत मामले ने पकड़ा तूल

सूरजपुर। सुरजपुर जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता और शिशु दोनों की मौत हो गई। घर में आने वाली रौनक, दुख का मंजर बन गया। अब इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीएमएचओ दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग भी की। आपको बता दें कि रामनगर गांव से प्रसव के लिए जिला अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई थी। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण महिला और बच्चे की जान चली गई। वहीं इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग टीमों का गठन किया है। एक टीम द्वारा पोस्टमार्टम प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी, जबकि दूसरी चार सदस्यीय टीम पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी।

सरपंच संघ ने एसपी दफ्तर घेरने की दी चेतावनी

बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सरपंच संघ ने एक बार फिर मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। संघ का आरोप है कि कुछ लोग स्वयं को पत्रकार बताकर सरपंचों को फोन पर धमकी दे रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इस मामले में पूर्व में शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर सरपंचों में नाराजगी बढ़ गई है। सरपंच संघ सदस्य अयुद नायक का कहना है कि 10 तारीख जून को धमकी के संबंध में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की गई थी। बावजूद इसके अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। मामले को गंभीर बताते हुए सरपंच संघ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सरपंच संघ ने चेतावनी दी है कि यदि अगले दो दिनों के भीतर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो जिलेभर के सरपंच एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेंगे और धरना-प्रदर्शन करेंगे।

बैठक में कलेक्टर रोक्तिमा यादव नशे के खिलाफ सख्त

कोरिया। जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर रोक्तिमा यादव की अध्यक्षता में नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) एवं नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।बैठक में जिले में मादक पदार्थों के सेवन, बिक्री, परिवहन, भंडारण और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिले में किसी भी कीमत पर अवैध नशे के कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा।

उन्होंने पुलिस, राजस्व, आबकारी, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण सहित सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने और तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रोक्तिमा यादव ने कहा कि नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध खेती, उत्पादन, भंडारण और परिवहन को रोकने के लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। पुनर्गठित व्यवस्था के तहत सूचनाओं के आदान-प्रदान और संयुक्त कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। बैठक में कलेक्टर ने वन विभाग को दूरस्थ एवं संवेदनशील वन क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध गांजा एवं अन्य मादक पदार्थों की खेती को रोकने के लिए बीट गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड नियमित निरीक्षण करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल प्रशासन और पुलिस को दें। जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र को निर्देश दिए गए कि ड्रग्स उत्पादन से संबंधित किसी भी उद्योग या इकाई की जानकारी संबंधित विभागों को समय पर उपलब्ध कराई जाए।

सिंथेटिक ड्रग्स के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर भी विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने आबकारी विभाग को अफीम, डोडाचूरा और अन्य मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।बैठक में लंबित गांजा प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने पूर्व से नष्टीकरण के लिए लंबित 206 गांजा प्रकरणों को अधिकृत समिति के माध्यम से शीघ्र नष्ट कराने के निर्देश दिए।समाज कल्याण विभाग को नशामुक्ति केंद्रों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने और युवाओं, विद्यार्थियों तथा नागरिकों के बीच लगातार जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग को बिना चिकित्सकीय पर्ची के नशीली दवाओं की बिक्री करने वाले मेडिकल स्टोर्स की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मेडिकल स्टोर्स की सरप्राइज जांच कर अनियमितता मिलने पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा गया। कलेक्टर ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की भागीदारी और व्यापक जनजागरूकता से ही जिले को नशामुक्त बनाया जा सकता है।

शिवनंदनपुर में शपथग्रहण पर सियासत

कांग्रेस के किसी भी बड़े लीडर का कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में नाम नहीं होने पर जताया एतराज, स्थरूको भी सौंपा ज्ञापन

सूरजपुर। जिले के नवगठित नगर पंचायत शिवनंदनपुर में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच भारी राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। दोनों पार्टियां इस मामले में आमने-सामने आ गई हैं। समारोह में प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहने वाले हैं तो ऐसे में कांग्रेस ने कार्यक्रम से अलग शपथग्रहण करने कि बात कही है। हाल ही में हुए चुनावों में कांग्रेस के 8 पार्षद जीतकर आए

कांग्रेस के पार्षद अलग से लेंगे शपथ

हैं, जबकि भाजपा के अध्यक्ष समेत 7 पार्षद जीते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि उनके ज्यादा पार्षद जीतने के बावजूद कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र (इनविटेशन कार्ड) में कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का नाम नहीं लिखा गया है। कांग्रेस इसे अपना अपमान मान रही है। ऐसे में कांग्रेस के जिला महामंत्री संजय डोसी ने कहा कि 8 पार्षद कांग्रेस के विजयी हुए हैं लेकिन कांग्रेस के किसी भी बड़े लीडर का कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में नाम नहीं है। इसे लेकर हमने स्थरूको ज्ञापन सौंपा है।इस मुख्य समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होने वाले हैं। भाजपा के दिग्गज नेता भीमसेन गोयल का कहना है कि जब मुख्यमंत्री और मंत्री आ रहे हैं, तो सरकारी नियम (प्रोटोकॉल) उन्हीं के हिसाब से तय होगा। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी आदेशों के तहत नियमों का पालन हो रहा है, और कांग्रेस को अलग शपथ लेनी है तो यह उनका फैसला है।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल डेका ने गजराज बांध को शहर की पेयजल आपूर्ति की दिशा में की पहल

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कमल विहार रायपुर स्थित लगभग 230 एकड़ क्षेत्र में फैले गजराज बांध को रायपुर शहर की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक विशाल जलाशय के रूप में विकसित करने की पहल की है। राज्यपाल ने आज लोकभवन में नगर निगम रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे और अतिरिक्त कमिश्नर श्री विनोद पाण्डेय के साथ इस संबंध में विशेष चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में सिंचाई कार्यो में उपयोग नहीं हो रहे गजराज बांध की आवश्यक मरम्मत कर इसे रायपुर शहर की लाइफलाइन बनाया जा सकता है। इस बांध को एक पेयजल भंड़ार के रूप में विकसित करने से शहर को शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।राज्यपाल ने महापौर से संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय कर इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देश दिए है।

नवा रायपुर जंगल सफारी में दिखा भारत का सबसे छोटा कठफोड़वा

रायपुर। नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी के बॉटेनिकल गार्डन में पक्षी प्रेमियों और प्रकृति संरक्षण से जुड़े लोगों के लिए एक सुखद समाचार सामने आया है। हाल ही में आयोजित बर्ड वॉक के दौरान वन्यजीव छायाकारों ने भारत के सबसे छोटे कठफोड़वों में से एक ब्राउन-कैप्ड पिग्मी वुडपैकर को कैमरे में कैद किया। तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्र में इस दुर्लभ पक्षी की मौजूदगी जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में नवा रायपुर का जंगल सफारी और बॉटेनिकल गार्डन जैव विविधता संरक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। यहां विकसित हरित वातावरण और संरक्षण उपायों के कारण अनेक पक्षी एवं वन्यजीवों को सुरक्षित आवास मिल रहा है। दुर्लभ पक्षियों की बढ़ती उपस्थिति इन प्रयासों की सफलता को दर्शाती है। ब्राउन-कैप्ड पिग्मी वुडपैकर भारत के सबसे छोटे कठफोड़वों में शामिल है। इसकी लंबाई लगभग 13 से 15 सेंटीमीटर होती है। यह पक्षी पेड़ों की छाल पर बेहद फुर्ती से चढ़ता-उतरता है और अपनी विशिष्ट गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इसके सिर पर भूरे रंग का मुकुटनुमा भाग तथा शरीर पर काले-सफेद धब्बेदार पंख होते हैं, जो इसे आकर्षक और आसानी से पहचानने योग्य बनाते हैं।

घुघरी कला नाला व्यपवर्तन योजना के लिए 4.58 करोड़ रूपए स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखंड शंकरगढ़ के अंतर्गत ग्राम घुघरी कला नाला में व्यपवर्तन योजना के निर्माण कार्य के लिए 4 करोड़ 58 लाख 75 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस महत्वाकांक्षी सिंचाई योजना के पूर्ण होने से स्थानीय किसानों को अपनी फसलों के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। योजना के तहत क्षेत्र में कुल 200 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए 180 हेक्टेयर क्षेत्र में सुविधा मिलेगी। वहीं लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलो कीं सिंचाई का लाभ किसान उठा सकेंगे। इस योजना के पूरा होने से शंकरगढ़ विकासखंड के ग्रामीण इलाकों में न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय किसानों की आर्थिक स्थिति में भी व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। इस परियोजना को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के लिए जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार (अम्बिकापुर) को आवश्यक प्रशासकीय निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

डिजिटल क्रांति से संवरती बुजुर्गों की राह

रायपुर। डिजिटल क्रांति बुजुर्गों के जीवन को आसान और आत्मनिर्भर बना रही है। ऑनलाइन पेंशन, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, और व्हाट्सएप आधारित सरकारी सेवाओं से उन्हें कतारों में लगने से मुक्ति मिली है। ग्रामीण अंचलों में सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी बाधा के हकदारों तक पहुँचाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। लेकिन जब तकनीक, संवेदनशीलता और ज़मीनी स्तर पर जागरूकता का मिलन होता है, तो सुदूर जंगलों और गाँवों में बदलाव की एक नई कहानी लिखी जाती है। कुछ ऐसी ही उम्मीद और बदलाव की बयार बही नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखंड के ग्राम पंचायत गारपा के आश्रित ग्राम मसपुर में। मसपुर में हाल ही में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक विशेष शिविर सिर्फ सरकारी या कागजी कार्रवाई का जरिया नहीं, बल्कि कई बुजुर्गों और आश्रितों के चेहरे पर मुस्कान लाने का माध्यम बना। यहाँ ग्रामीणों को आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की ताक़त से रूबरू कराया गया। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में यह चिंता बनी रहती है कि पेंशन कब आएगी और कैसे मिलेगी? इस शिविर ने इसी अनिश्चितता को दूर किया। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ने खुद ग्रामीणों के बीच पहुँचकर बेहद सरल भाषा में समझाया कि कैसे उनका आधार कार्ड और बैंक खाता मिलकर उनकी पेंशन को सुरक्षित बनाता है।

डबल इंजन सरकार के प्रयासों से रेल कनेक्टिविटी का हो रहा अभूतपूर्व विस्तार: साय

755 करोड़ रूपए की परियोजना को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी एवं रेल मंत्री के प्रति जताया आभार

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भारतीय रेल द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 755 करोड़ रूपए की लागत से चांपा-कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह परियोजना छत्तीसगढ़ के विकास, औद्योगिक प्रगति और देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में रेल अधोसंरचना का निरंतर विस्तार हो रहा है, जिससे विकास को नई गति मिल रही है।

उन्होंने कहा कि परियोजना के पूरा होने पर यात्री सुविधाओं में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। अतिरिक्त रेल लाइन उपलब्ध होने से ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुचारु होगी, परिचालन संबंधी बाधाएं कम होंगी तथा भविष्य में अतिरिक्त यात्री ट्रेनों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे आम नागरिकों को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक रेल सेवाएं प्राप्त होंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कोरबा देश की ऊर्जा राजधानी के रूप में महत्वपूर्ण पहचान रखता है और यहां से देश के विभिन्न हिस्सों तक कोयले की आपूर्ति होती है। चांपा-कोरबा रेल खंड साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) तथा महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की खदानों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस परियोजना के पूर्ण होने से कोयला परिवहन की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक आधार और अधिक मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में तीसरी रेल लाइन का निर्माण भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया दूरदर्शी निर्णय है। इससे अतिरिक्त माल परिवहन को सुगम बनाया जा सकेगा और रेल परिचालन अधिक दक्ष एवं प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह परियोजना केवल कोयला परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी व्यापक लाभ मिलेगा। बेहतर रेल संपर्क से उद्योगों को मजबूती मिलेगी, निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी, व्यापारिक गतिविधियों का

विस्तार होगा तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इससे कोरबा, जांजगीर-चांपा सहित आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि चांपा-कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति को नई ऊर्जा प्रदान करेगी तथा विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि मजबूत रेल नेटवर्क, सुदृढ़ लॉजिस्टिक व्यवस्था और बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से छत्तीसगढ़ देश के विकास में और अधिक प्रभावी योगदान देने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत वर्षों में छत्तीसगढ़ को रेल अधोसंरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्राथमिकता मिली है। प्रदेश के रेल बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा नई रेल लाइनों, दोहरीकरण, तीसरी-चौथी लाइन और आधुनिक रेलवे स्टेशनों के विकास के माध्यम से कनेक्टिविटी को लगातार सशक्त किया जा रहा है। हाल ही में धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा रेल परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया जाना भी इसी विकास दृष्टि का प्रमाण है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा रेल परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में स्वीकृति मिलना जशपुर सहित पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विशेष स्नेह और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। लंबे समय से रेल संपर्क की प्रतीक्षा कर रहे जशपुरांचल को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह परियोजना केवल एक रेल लाइन नहीं, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास की नई आधारशिला है। इससे पर्यटन, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा वनांचल क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से और अधिक मजबूती से जुड़ सकेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में रेल एवं शहरी परिवहन अधोसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना के विकास पर 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1853 से 2014 तक 161 वर्षों में छत्तीसगढ़ में लगभग 1100 रूट किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई थी, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश का रेल नेटवर्क बढ़कर 2200 रूट किलोमीटर से अधिक होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रदेश की रेल परियोजनाओं के लिए जहां लगभग 300 करोड़ रुपये का बजट मिलता था, वहीं वर्ष 2026-27 में यह बढ़कर 7,470 करोड़ रुपये हो गया है। साथ ही प्रदेश के 32 रेलवे स्टेशनों को 1,680 करोड़ रुपये की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम है।

रेत के खूनी खेल पर मुख्यमंत्री साय का बड़ा बयान, बोले-

किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा

रायपुर। कोरिया जिले में रेत उत्खनन को लेकर हुए विवाद में भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार और उनके करीबी वीरू सिंह गहरवार की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस मामले में आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि मंगलवार को कोरिया जिले में रेत उत्खनन को लेकर भाजपा नेताओं के बीच विवाद हुआ था, जो रात में खूनी संघर्ष में बदल गया। इस दौरान फॉर्च्यूनर वाहन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, जिसमें भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार की मौके पर जलकर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसे उनके रिश्तेदार वीरू सिंह की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं इस घटना में तीन अन्य घायलों का अंबिकापुर अस्पताल में इलाज जारी है। इनमें से एक योगेन्द्र सिंह बोलने की स्थिति में है।

दरअसल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर से सूरजपुर दौरे के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए इस सनसनीखेज घटना पर प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर भी बयान

दिया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि वह सूरजपुर दौरे पर जा रहे हैं, जहां नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा गरियाबंद जिले में करीब 600 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा।

चांपा-कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा राशि स्वीकृत किए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत आभार है।

आगामी 13 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विपक्ष का काम है कहना, वे अपना धर्म निभाएंगे।

रायपुर में विमान हादसा टला, फ्लाइट पक्षी से टकराई

- 2 घंटे तक उड़ानें हुई प्रभावित

रायपुर। माना स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर बुधवार की सुबह 8.30 बजे एक हादसा टल गया। एयर इंडिया का विमान रायपुर एयरपोर्ट पर रनवे से उतरते समय एक पक्षी से टकरा गया। इस घटना के बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान उड़ाने दो घंटा लेट हुई। घटना के तुरंत बाद एयरपोर्ट प्रबंधन की तकनीकी टीम सक्रिय हो गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जरूरी कदम उठाया गया।

रनवे पर उतरते समय एयर इंडिया का विमान एक पक्षी से टकरा गया। इस घटना में एयर इंडिया के विमान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। घटना के तुरंत बाद एयरपोर्ट प्रबंधन की तकनीकी टीम सक्रिय हो गई। फ्लाइट में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

जानकारी के मुताबिक यह विमान दिल्ली से रायपुर पहुंचा था। लैंडिंग के

दौरान हुई इस घटना के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जरूरी कदम उठाए। विमान को सुरक्षित तरीके से पार्किंग एरिया पर ले जाया गया। जहां उसकी तकनीकी जांच की गई।

बर्ड हिट की घटना के बाद सुरक्षा को देखते हुए रनवे और विमान की जांच की गई। तकनीकी टीम की अनुमति मिलने तक कुछ समय के लिए उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा, जिसके चलते रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होने वाली फ्लाइट 2 घंटे देरी से उड़ान भर सकी। देरी की वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार करना पड़ा।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रायपुर के असिस्टेंट जनरल मैनेजर संदीप राठौर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह एक सामान्य घटना है और महीने में इस तरह की तीन से चार बर्ड हिट की घटना होती है।

बारिश के दिनों में बर्ड हिट की घटना बढ़कर 8 से 10 तक हो जाती है। क्योंकि बारिश के दिनों में पानी गिरने के बाद पक्षी कीड़ा खाने के लिए नीचे आते हैं। फ्लाइट लैंडिंग के समय पक्षी विमान से टकरा जाते हैं। इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एयरक्राफ्ट से बर्ड टकराता है तो एसओपी फॉलो करने के 2 घंटे के बाद फ्लाइट अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गया।

संदीप राठौर ने कहा इस घटना के बाद रायपुर एयरपोर्ट के अधिकारियों ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जांच प्रक्रिया पूरी की। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार किसी भी यात्री को परेशानी ना हो इसके लिए जरूरी व्यवस्थाएं भी एयरपोर्ट पर की गई थी।

किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसका मानव संसाधन होती है: उद्योग मंत्री

रायपुर। वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन आज रायपुर में डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय (बिलासपुर) एवं आइसेक्ट इंडिया ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित दो दिवसीय समर्थ भारत कॉन्क्लेव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री देवांगन ने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसका मानव संसाधन होती है। भारत के पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है, लेकिन चुनौती है उन्हें आज के दौर के अनुसार हुनरमंद बनाना। श्री देवांगन ने कहा कि आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां परिवर्तन ही एक मात्र स्थिर चीज है और इस दौर में भारत को एक महा शक्ति बनाने का सबसे बड़ा सारथी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.)।

विकसित भारत के लिए ए.आई. संचालित कौशल विकास वित्तीय समावेशन और सामाजिक उद्यम विषय पर आईसेक्ट द्वारा इसका आयोजन किया गया। केबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि जब हम साल 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की बात करते हैं तो ए.आई. केवल एक तकनीक नहीं बल्कि वह इंजन है जो हमारे कौशल, हमारी

अर्थव्यवस्था और हमारे समाज को नई दिशा और रफतार देगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तब तक अधूरा है जब तक विकास की रोशनी देश के आखरी कोने में बैठे व्यक्ति तक न पहुंचे। वित्तीय समावेशन का मतलब है, हर नागरिक को बैंकिंग और आर्थिक व्यवस्था से जोड़ना। श्री देवांगन ने कहा कि आजकल सामाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति मोबाइल ऐप के माध्यम से सरकार के समस्त योजनाओं की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकता है। यह केवल तकनीकि उत्थान एवं ए.आई. के माध्यम से संभव हो सका है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने 5 युवा उद्यमियों को सम्मानित किया।

जैविक खेती से गांव होंगे समृद्ध, किसान बनेंगे आत्मनिर्भर: साव

- जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले किसानों का किया गया सम्मान

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने आज बिलासपुर में कृषि विभाग की एक्सटेंशन रिफॉर्म्स (आत्मा) योजना अंतर्गत कृषि महाविद्यालय में आयोजित जैविक कृषि कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यशाला में कहा कि जैविक खेती से गांव समृद्ध होंगे और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। उप मुख्यमंत्री ने किसानों से जैविक खेती अपनाने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता संतोष कश्यप, सभापति श्रीमती अंबालिका साहू, श्रीमती अनुसुईया जागेंद्र कश्यप, रतनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री लवकुश कश्यप, नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल, डॉ आर.के.एस. तोमर, श्री राजेश सिंह, श्री

राकेश तिवारी, श्री धीरेंद्र दुबे और श्री दिनेश कौशिक सहित कृषि वैज्ञानिक, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि किसान धरती पुत्र हैं। कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि गांवों की समृद्धि, किसानों की खुशहाली और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैविक खेती समय की आवश्यकता है, क्योंकि रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव भूमि की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य दोनों पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने किसानों से जैविक खेती को अपनाने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा पशुपालन और गौसंवर्धन को कृषि व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गांवों में आपसी सहयोग और सामुदायिक सहभागिता से ही आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है जिनसे किसानों को आर्थिक संबल मिला है। उन्होंने कहा कि गांवों को फिर से समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति गांव, किसान और जनभागीदारी में निहित है।

21 जून को प्रदेश में 'स्वस्थ आयु के लिए योग' थीम पर होगा विशेष कार्यक्रम

- जिला मुख्यालयों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सांसदगण एवं विधायकगण होंगे मुख्य अतिथि

रायपुर। 21 जून 2026 को इस बार स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को लेकर जिला मुख्यालयों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला मुख्यालयों में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री द्वय, मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण मुख्य अतिथि होंगे। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले सामूहिक योगाभ्यास में मुख्य अतिथि नामांकित किया गया है।

राज्यपाल श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में 21 जून को राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे।

जारी आदेश के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू बिलासपुर में, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव दुर्ग में, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा कबीरधाम, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि होंगें। इसी प्रकार कोरिया जिले में मंत्री श्री रामविचार नेताम, महासमुंद जिले में मंत्री श्री दयालदास बघेल, सुकमा जिले में

मंत्री श्री केदार कश्यप, कांकेर जिले में मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, जांजगीर-चांपा जिले में मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में मंत्री श्री टंकराम वर्मा, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, जशपुर जिले में मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, कोरबा जिले में मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब और बालोद जिले में मंत्री श्री गजेन्द्र यादव 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि बनाए गए हैं।

विभिन्न जिलों में योग दिवस के गरिमामय आयोजन की कमान माननीय सांसदों और विधायकों में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, बेमेतरा जिले में सांसद श्री विजय बघेल, मोहला-मानपुर-चौकी जिले में सांसद श्री संतोष पांडेय 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। इसी प्रकार सूरजपुर जिले में सांसद श्री चिंतामणी महाराज, गरियाबंद जिले में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, रायगढ़ जिले में सांसद श्री राधेश्याम राठिया, जांजगीर जिले में सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, नारायणपुर जिले में सांसद श्री महेश कश्यप और कोण्डागांव जिले में सांसद श्री भोजराज नाग 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे।

बीजापुर जिले में विधायक सुश्री लता उसेंडी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में विधायक श्री ललित चंद्राकर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची, मुंगेली जिले में विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले, धमतरी जिले में विधायक श्री अजय चंद्राकर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में विधायक श्रीमती रेणुका सिंह, बस्तर जिले में विधायक श्री किरण सिंह देव और दंतेवाड़ा जिले में विधायक श्री चौतराम अटामी को 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बनाए गए हैं। सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सामूहिक योग कार्यक्रमों की तैयारियां जिला प्रशासन की देखरेख में अंतिम चरण में हैं।

अब सत्ता ही है राजनीति की वास्तविक विचारधारा

पूनम आई. कौशिश

किसी राष्ट्र को सस्ते राजनेता से अधिक महंगा कुछ नहीं पड़ता। यह कहावत आज के राजनीतिक मौसम में पूरी तरह चरितार्थ होती दिखती है, जहां दल-बदल का दौर अपने चरम पर है। यह समझना कठिन हो गया है कि कौन किसके साथ है, कौन किसका साथ छोड़ रहा है, कौन किस दल में प्रवेश कर रहा है और कौन किससे समझौते कर रहा है। सब कुछ केवल सत्ता प्राप्ति के लिए हो रहा है। यह समस्या ममता बनर्जी की पार्टी के लिए भी चुनौती बनी हुई है, जिसने कई सांसदों और विधायकों को खोया। इसी प्रकार केजरीवाल की पार्टी तथा महाराष्ट्र में अन्य दलों को भी टूट-फूट का सामना करना पड़ा। एक दल-बदल कर चुके नेता ने स्वीकार किया, ''जब भाजपा राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर एक प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी, तो हमें एक अधिक संसाधन-संपन्न प्रतिद्वंद्वी के दबाव का सामना करना पड़ा। ऐसे में केवल प्रासंगिक बने रहना ही नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व बचाना भी चुनौती बन गया। इसलिए हमने दल बदलने का निर्णय लिया।'' प्रश्न यह है कि किसी राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है? क्या वह अपनी पहचान और विचारधारा को सुरक्षित रखने के लिए होता है? क्या वह बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए होता है? या फिर राजनीति का अंतिम लक्ष्य केवल चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्त करना ही है? नि:संदेह, जब सत्ता राजनीति का अंतिम लक्ष्य बन जाती है, तब विचारधारा के लिए बहुत कम स्थान बचता है। सत्ता वह माध्यम है, जिसके द्वारा दल अपनी नीतियों को लागू करते हैं। सत्ता के बिना विचारधारा केवल विचारों का संग्रह बनकर रह जाती है। किंतु जब सत्ता की प्राप्ति ही सर्वोपरि उद्देश्य बन जाए, तब विचारधारा गौण, लचीली अथवा त्याज्य बन जाती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सत्ता प्राप्ति के लिए विचारधारा से कितना समझौता स्वीकार्य है? सांसदों और विधायकों का अपने मतदाताओं से क्या संबंध है? क्या वे केवल प्रतिनिधि हैं या उनके बीच कोई नैतिक दायित्व भी है, जिसे अब भुला दिया गया है? दुर्भाग्यवश, नेताओं की विश्वसनीयता लगातार गिर रही है। सत्ता की लालसा इतनी प्रबल हो गई है कि नेता विपक्ष में रहते हुए विचारधारा की दुहाई देते हैं लेकिन सत्ता सामने आते ही उसे किनारे रखने को तैयार हो जाते हैं। कथनी और करनी के बीच का यही अंतर इस निष्कर्ष को जन्म देता है कि राजनीति की वास्तविक विचारधारा अब सत्ता ही है। फिर भी क्या इसे केवल राजनीतिक कलियुग कहकर टाल देना पर्याप्त है? यदि सत्ता की राजनीति ने विचारधारा को पीछे छोड़ दिया है, तो समाधान राजनीति को त्यागने में नहीं, बल्कि सत्ता को पुन: उद्देश्य से जोडने में है। राजनीतिक दलों को ऐसे मूलभूत सिद्धांत निर्धारित करने होंगे, जिन पर कोई समझौता न किया जा सके। रणनीति, गठबंधन और नीतियों में लचीलापन हो सकता है लेकिन मूल मूल्य नहीं छोड़े जाने चाहिएं। आदर्श रूप से कोई भी दल कुछ विचारों, नीतियों और जनहितों को आगे बढ़ाने का माध्यम होता है, केवल अपने संगठनात्मक अस्तित्व को बनाए रखने का साधन नहीं। व्यवहार में, दलों के सामने 2 विकल्प होते हैं-अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना या चुनावी सफलता के लिए समझौते करना। जो दल किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते, वे सिद्धांतवादी तो बने रहते हैं, परंतु नीति-निर्माण को प्रभावित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति इन दोनों के बीच संतुलन का निरंतर प्रयास है। आज भारत एक नैतिक चौराहे पर खड़ा है। झूठ, छल और भ्रम के इस खेल में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सभी दल एक कड़वी सच्चाई को प्रतिबिंबित करते हैं-सत्ता ही सब कुछ है।

बागी गुट का यह 'दल शोधन' कहीं उल्टा न पड़ जाए

अजय बोकिल

इसे दुरभिसंधि कहें या फिर राजनीतिक नवाचार, लेकिन भारतीय राजनीति में 'दल शोधन' का यह नया प्रयोग अपनी मूल पार्टी भारतीय राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए बागियों के गुट और परदे के पीछे इसकी सूत्रधार भाजपा को भारी न पड़ जाए। क्योंकि टीएमसी के बागी 20 सांसदों के एक अनजान से राजनीतिक दल 'नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (एनसीपीआई) में 'विलय' और कथित विलय के बाद इस गुट को संसद में अलग बैठने की इजाजत स्पीकर ओम बिरला ने अभी नहीं दी है। कहने को यह रास्ता बागी सांसदों के भाजपा में विलय की कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए निकाला गया है, लेकिन खुद इस रास्ते में कई कांटे हैं। हालांकि जो कुछ हो रहा है, उससे देश में उन तमाम रजिस्टर्ड मगर चुनाव आयोग से गैर मान्यता प्राप्त सियासी पार्टियों की उम्मीदें बढ़ गई थीं, जो राजनीतिक कूड़े दान में पड़ी थीं। क्योंकि उनके दिन भी फिर सकते हैं।

अगर इस बागी गुट के विलय को संसद में अलग बैठने की मान्यता मिल गई तो जो पार्टी कल तक मच्छर की हैसियत भी नहीं रखती थी, वो आज 20 सांसदों के साथ मगरमच्छ की तरह अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को डराने की स्थिति में होगी। हम अभी तक अर्थशास्त्र में शेल कंपनियों (मुखौटा अथवा खोखा कंपनियां की बात सुनते थे, जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड तो होती हैं, लेकिन उन्हें केवल धन शोधन (मनीलांड्रिंग), काले धन को सफेद करने, पैसों की हेराफेरी तथा कर अपवंचन की नीयत से बनाया जाता है। लेकिन अब भाजपा के पश्चिम बंगाल मॉडल के तहत राजनीतिक 'दल शोधन' (पॉलिटिकल पार्टी लांड्रिंग) का नया जुमला वजूद में आ गया है। हालांकि इस 'दल शोधन फार्मूले' की कामयाबी में कई कानूनी और संवैधानिक पेंच हैं, लेकिन यह सफल हो गया तो हमे भविष्य में इसके नए एप्लीकेशन भी देखने को मिल सकते हैं।

नैतिक दृष्टि से इस 'दल शोधन' फार्मूले की आलोचना हो रही है। क्योंकि यह निष्ठाहीन, सिद्धांतविहीन सत्ताकेन्द्रित राजनीति को वैधता प्रदान करने जैसा है। खुद भाजपा में भी इसके औचित्य पर लोग प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक जब आर्थिकी में इस तरह का धन शोधन अनुचित है तो राजनीति में इस दल शोधन को कैसे उचित माना जा सकता है? इस 'दल शोधन' ने देश में दलबदल कानून की प्रभावशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अगर यानी कानूनी की पतली गलियां ही ज्यादा असरदार हैं तो ऐसे कानून का क्या मलतब? हालांकि भाजपा जैसी साधन से ज्यादा साध्य को परम मानने वाली पार्टी की सोच है कि तात्कालिक राजनीतिक लाभ किसमें यह देखना अहम है, न कि इसके दीर्घकालीन औचित्य-अनौचित्य के बारे में सोचना। पार्टी का मानना है कि संसद में मोदी सरकार द्वारा दो माह पूर्व लाए गए महिला आरक्षण और परिसीमन बिल दो तिहाई बहुमत के अभाव में गिर गए थे, उन्हें पास कराने के लिए किसी भी तरीके से संख्या बल जुटाना है। और इस ' पुनीत' कार्य को पूरा करने के लिए साम-दाम-दंड-भेद सब जायज है। हालांकि 'दल शोधन' इन पारंपरिक चार कारकों से भी अलग है।

इस स्तम्भ में पहले भी लिखा जा चुका है कि बीजेपी का राजनीतिक पश्चिम बंगाल मॉडल उसके पूर्ववर्ती मॉडलों की तुलना में अलग होगा, फिर भी इतना ज्यादा अलग होगा, यह राजनीतिक प्रेक्षकों के सोच के परे की बात रही है। माना यही जा रहा था कि भाजपा महाराष्ट्र मॉडल की तरह बंगाल में अब विपक्ष में बैठी टीमएमसी को तोड़कर नया गुट बनवाएगी या फिर उसे अपने में मर्ज कर लेगी। लेकिन ऐसा करने में कई कानूनी जटिलताएं और किंतु परंतु हैं और वक्त कम है, क्योंकि भाजपा को अर्जुन की तरह 2029 का लोकसभा चुनाव दिखाई दे रहा है। लिहाजा पुराने नुस्खों की जगह दूर की कौड़ी लाई गई।

त्रिपुरा में रजिस्टर्ड एक गुमनाम सी पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' पर दांव खेला गया। यह पार्टी त्रिपुरा के कुंडू दंपति और शांतनु डे ने 20 जनवरी 2023 को मजे-मजे में रजिस्टर्ड कराई थी। इसका मुख्यालय हावड़ा में है। लेकिन उसे चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली है। एनसीपीआई ने उसी साल त्रिपुरा विस चुनाव में दो सीटों पर चुनाव लड़ा। सात किरणों वाली पेन की निब इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। चुनाव में उसे कुल जमा 822 वोट और 1.13 लाख रू. का चुनावी चंदा मिला। पति उत्तीय कुंडू और पत्नी शिवली कुंडू खुद को समाज सेवी बताते हैं। शिवली पहले कोषाध्यक्ष थीं, अब वो उससे अलग हो गई हैं। अब सवाल यह कि टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों के गुट को संसद में अलग मान्यता दिलाने की जगह एक अज्ञातकुलशील पार्टी में विलय का विचार कैसे और कहां से आया? ये सौदेबाजी किसने की? उत्तीय कुंडू का भाजपा से क्या सम्बन्ध है? यह चमत्कारिक विलय इतने गोपनीय ढंग से कैसे हो गया? और क्या ऐसा विलय जायज है? इस पार्टी का अध्यक्ष पद भी बागी सांसदों में से एक ज्योतिप्रकाश चटर्जी के पास कैसे चला गया और पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष उत्तीय कुंडू ने खुशी खुशी अपनी पार्टी को हाई जैक कैसे हो जाने दिया? इसके पीछे कौन सा लेन-देन अथवा अंडरस्टैंडिंग बनी? सवाल कई हैं।

फिलहाल तो भाजपाई अपने इस नवाचारी दांव पर मुग्ध हैं। लेकिन जानकार इसकी वैधानिकता और स्थायित्व पर सवाल उठा रहे हैं। पहला और अहम सवाल तो यही है कि यही है कि क्या टीएमसी के चुनाव चिह्न और टिकट पर लोकसभा पहुंचे ये सांसद खुद को किसी और पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं या नहीं? क्या संसद सदस्यों (या विधायकों) का कोई समूह खुद को अलग करके दूसरे राजनीतिक दल के साथ विलय कर सकता है या नहीं? या इसके लिए जिस राजनीतिक दल से वो निर्वाचित हुए हैं उसका सहमत होना आवश्यक है?

संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य के मुताबिक इस मामले में कानून स्पष्ट है कि किसी राजनीतिक दल का तो विलय हो सकता है लेकिन निर्वाचित सदस्यों के समूह का नहीं, भले ही उनकी संख्या दो-तिहाई से अधिक हो। बागी सांसद चूंकि सांसद तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुने गए हैं, इसलिए उन पर दल-बदल विरोधी कानून लागू होगा। वे अपनी मर्जी से किसी भी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, अगर वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन यदि चुनाव आयोग इन बागी सांसदों के दल को ही मूल तृणमूल कांग्रेस घोषित कर देता है तब यह क़ानून लागू नहीं होगा। आचार्य के मुताबिक मौजूदा क़ानून के तहत बागी निर्वाचित सदस्यों की संख्या का कोई अर्थ नहीं है। कानून कहता है कि पहले मूल पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय होगा, फिर उसके सदस्य नए दल में शामिल सकते हैं। यानी बागी सांसद भले ही खुद के एनसीपीआई में विलीन होने की घोषणा कर रहे हों लेकिन क़ानूनन वे टीएमसी के सदस्य ही हैं।

इसका सीधा अर्थ यह है कि 'दल शोधन' का यह रास्ता भारी जोखिमों से भरा है। राजनीतिक विश्लेषकों का तो कहना है कि यदि इस कथित विलय को मंजूरी मिल जाती है तो इसके गंभीर राजनीतिक मायने होंगे। यानी बड़ा झटका क्षेत्रीय पार्टियों को लगेगा। यह दल शोधन उनके राजनीतिक विनाश की घंटी है। जहां तक उत्तीय कुंडू और भाजपा के रिश्तों की बात है तो बंगाल में भाजपा की बंपर जीत के बाद उत्तीय कुंडू ने 13 मई को अपने फेसबुक पेज पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के साथ एक तस्वीर साझा की थी। इसका बंगाली में कैप्शन था 'सिर्फ सपने देखने के दिन खत्म हो गए हैं, अब उन्हें सच करने का समय है।

इसी तरह टीएमसी के बागी सांसदों के विलय से पहले उत्तीय ने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा की। इसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें थीं। पोस्ट में लिखा था, अहंकार पतन का कारण बनता है। सत्ता के नशे में लोग अक्सर भूल जाते हैं कि सत्ता स्थायी नहीं होती और जनता का समर्थन ही असली ताकत हैज्जो आज शिखर पर हैं, उन्हें कल समय को जवाब देना होगा। जाहिर है टीएमसी बागी गुट के विलय की पटकथा लिखने में उत्तीय और शुभेंदु की बड़ी भूमिका लगती है। दूसरी तरफ टीएमसी बागी गुटों में भी सांसद और विधायक अलग अलग राह चल रहे हैं। जबकि पार्टी पर ममता बैनर्जी की पकड़ अभी बहुत कमजोर नहीं हुई है। बहरहाल इस 'दल शोधन' का अंजाम क्या होगा, ये देखना दिलचस्प है। कहीं 'धन शोधन' की तरह यह भी भारी न पड़ जाए।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

है और अपने इस कार्य का न केवल वाचिक बल्कि-200 पृष्ठ की लम्बी चौड़ी माँस भोजन विचार नामक पुस्तक छपाकर वेदमन्त्रों द्वारा खुला समर्थन करती है। उदाहरणार्थ इस पुस्तक से एक आध उद्धरण नीचे देते हैं। जल और घी से पकाया हुआ बकरा सर्वोत्तम खाना है। इससे मुखप्रकाश और ज्ञानादियुक्त धर्मलोक प्राप्त होते हैं। (पृष्ठ 86)

बकरे के जघन के माँस से सिद्ध भात को पश्चिम दिशा में घरो, दूसरे भाग, के पकाये भात को कुक्षिस्थ माँस से पकाये भात को बकरे के बकरी वाले स्थान से सिद्ध भात को मध्य घाग के पकाये भात को पूर्वादि दिशानों में घरो (पृष्ठ 87)

यह पुस्तक जोधपुर (मारवाड़) के आर्यसमाज ने छपाई है। महात्मा हंसराज और प्रोफेसर दीवानचन्द (लाहौर) आदि प्रसिद्ध दयानन्दी नेता डंके की चोट इसके समर्थक हैं। जरा आंख खोलकर देख लीजिये कि निराकार बाबा को भोग लगाने के लिये किस प्रकार पूर्वादि दिशाओं में बकरे के वभिन्न भागों (यहाँ तक कि गुह्य न्द्रिय) के मांस की बलि दी जा रही है। सम्भव है आप इसको एक पार्टी का कृत्य बताकर स्वा0 दयानन्द और अपनी पार्टी का दाष परिमार्जन करना चाहें परन्तु ध्यान रहे स्वामी दयानन्द अपने यजुर्वेद भाष्य में मांस के हवन द्वारा निराकार की पूजा करना और बचा हुआा स्वयं खाना समा-जियों के लिये स्पष्ट लिख गये हैं, यथा- जो इस संसार में बहुत पशु वाला होम करके हुतशेष का भोक्ता वेदवित्, और सत्य क्रिया का कर्ता मनुष्य होवे सो प्रशंसा को प्राप्त होता है (यजुर्वेदीय दयानन्द भाष्य 16 । 20)

जुआ खेलने की आज्ञा

कुर्यान्महोत्सवं राजा दिनानि नव सप्त वा।
वैश्या ङ्गनान रैह ष्टे द्यूतक्रीडामहोत्सवैः।।
(भविष्यपुराण उत्तरपर्व 4 अध्याय 136)

क्रमशः ...

रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस

अभिलाष श्रीवास्तव

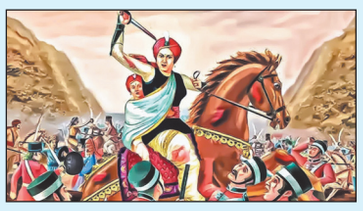

भारत के गौरवशाली इतिहास में जब-जब वीरांगनाओं का जिक्र किया जाएगा, महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता और पराक्रम हमेशा लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। कवियित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी रचना झांसी की रानी में इसी पराक्रम का जिक्र करते हुए लिखा था- खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आज पुण्यतिथि है। 18 जून सन् 1858 को अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थीं। हर साल 18 जून का दिन रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के रूप में उनके शौर्य की याद दिलाता है।

रानी लक्ष्मीबाई ने उस दौर में अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे, जब युद्ध के लिए सिर्फ पुरुषों को योग्य माना जाता था। रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल के साथ उनका मातृत्व धर्म भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है।

1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह वह समय था जब भारतीय सैनिकों और जनसमूह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह में लक्ष्मी बाई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी।

जब 1857 में विद्रोह शुरू हुआ, लक्ष्मी बाई ने झांसी को सुरक्षित रखने के लिए अपनी सेना का संगठन किया। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया और उनकी सेना में शामिल किया। उनके नेतृत्व और सैन्य रणनीति ने अंग्रेजों के लिए झांसी पर कब्जा करना मुश्किल बना दिया।

मार्च 1858 में, ब्रिटिश सेना ने सर ह्यूग रोज के नेतृत्व में झांसी पर आक्रमण किया। रानी लक्ष्मी बाई ने अपने किले की रक्षा के लिए वीरता से लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई तीन सप्ताह तक चली। इस दौरान रानी लक्ष्मी बाई ने कई साहसिक निर्णय लिए और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने अपने किले की रक्षा के लिए सभी संभव उपाय किए, लेकिन ब्रिटिश सेना की संख्या और संसाधनों के सामने उनकी सेना कमजोर पड़ने लगी।

झांसी के किले में अंग्रेजों के प्रवेश के बाद, लक्ष्मी बाई ने अपनी सेना के साथ किले से बाहर निकलने का साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर किले से बाहर निकलते हुए अंग्रेजों का सामना किया। रानी लक्ष्मी बाई और उनकी सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ कई अन्य लड़ाइयाँ लड़ीं। उन्होंने कालपी और ग्वालियर में भी अंग्रेजों से मुकाबला किया।

18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में, रानी लक्ष्मी बाई ने अंग्रेजों के साथ अंतिम युद्ध लड़ा। इस युद्ध में उन्होंने अपने अद्वितीय साहस का परिचय दिया और वीरगति प्राप्त की। उनकी मृत्यु ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया जोश भरा और उनके बलिदान ने भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित की।

जी-7 क्या है? इसके वैश्विक मायने क्या हैं?

कमलेश पांडे

दुनिया के अस्ताचलगामी शक्तिशाली देशों के रणनीतिक संगठन जी-7 की शिखर बैठक फ्रांस के एवियां (Évian-les-Bains) शहर में 15ङ्क17 जून 2026 तक आयोजित हुई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसी बैठ में सवा साल मोदी-ट्रंप की भी मुलाकात हुई, जिसका अपना बहुपक्षीय महत्व है। जी-7 क्या है? इसके वैश्विक मायने क्या हैं? और दुनिया के विभिन्न महत्वपूर्ण देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी चुनौतियां क्या हैं और किस बात के लिए आलोचनाएं होती हैं? जवाब निम्नलिखित है-

जी-7 में सात प्रमुख औद्योगिक लोकतांत्रिक देश शामिल हैं- संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। इसके अलावा यूरोपीय संघ भी स्थायी भागीदार के रूप में शामिल होता है। यह कोई औपचारिक अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है; इसका न तो कोई संविधान है और न ही स्थायी सचिवालय।

जी-7 शिखर सम्मेलन का सबसे से बड़ा भू-राजनीतिक संदेश : 2026 का फ्रांस जी-7 शिखर सम्मेलन यह संकेत देता है कि विश्व व्यवस्था अब केवल अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब तीन बड़े मुद्दे एक साथ उभर रहे हैं:- एक, सुरक्षा (यूक्रेन, मध्य पूर्व); दो, अर्थव्यवस्था (वैश्विक असंतुलन, सप्लाई चेन); और तीन, प्रौद्योगिकी (एआई, डिजिटल शासन)। यदि जी-7 इन तीनों क्षेत्रों में साझा रणनीति बना पाता है, तो आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति-संतुलन पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों और उनके साझेदारों (भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि) के पक्ष में झुक सकता है। वहीं चीन और रूस को अपने वैकल्पिक गठबंधनों को और मजबूत करना पड़ेगा।

जी 7 शिखर बैठक के प्रमुख वैश्विक मायने निम्नलिखित हैं, जिन्हें समझकर और साधकर कोई भी देश आगे बढ़ सकता है। पहला, यूक्रेन-रूस युद्ध पर पश्चिमी एकजुटता की परीक्षा: जी-7 देशों ने

यूक्रेन को समर्थन जारी रखने और रूस पर दबाव बनाए रखने पर चर्चा की। यूक्रेनी राष्ट्रपति ब्लादिमीर जैलेंस्की की मौजूदगी ने संकेत दिया कि यूरोप चाहता है कि युद्ध का समाधान यूक्रेन की शर्तों के अनुरूप हो। लिहाजा इसका प्रभाव यह होगा कि रूस पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ सकता है।

यूरोपीय सुरक्षा ढांचे में नाटो की भूमिका और मजबूत हो सकती है। वैश्विक हथियार एवं रक्षा उद्योग को लाभ मिल सकता है। भू-राजनीतिक संकटों पर सामूहिक प्रतिक्रिया: रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया की स्थिति, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और प्रतिबंधों जैसे मुद्दों पर जी-7 देशों की सामूहिक रणनीति अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है।

दूसरा, अमेरिका-ईरान समझौते के बाद पश्चिम एशिया की नई राजनीति: यह सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक शांति समझौता सामने आया है। जी-7 नेताओं ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर विशेष चर्चा की। इसका प्रभाव यह होगा कि अरब-खाड़ी देशों को राहत मिल सकती है। तेल कीमतों में स्थिरता आ सकती है। ईरान के वैश्विक आर्थिक पुनर्समावेशन की संभावना बढ़ सकती है।

तीसरा, चीन के लिए स्पष्ट संदेश: फ्रांस की अध्यक्षता वाले जी-7 का प्रमुख एजेंडा वैश्विक आर्थिक असंतुलन और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा है, जिसे व्यापक रूप से चीन पर निर्भरता कम करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इसका प्रभाव यह होगा कि चीन पर व्यापारिक दबाव बढ़ सकता है। फ्रेंड-शोरिंग और चाइना+1 रणनीति को बल मिलेगा। भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया और मेक्सिको जैसे देशों को निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। हाल के वर्षों में जी-7 चीन की औद्योगिक क्षमता, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और वैश्विक निवेश पहलों के विकल्प तैयार करने पर जोर दे रहा है।

चौथा, एआई और डिजिटल शासन पर वैश्विक नियमों की दिशा: जी-7 में एआई के भविष्य, डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नियमन पर भी चर्चा हुई। इसका प्रभाव यह होगा कि एआई के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक विकसित हो सकते हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ सकता है। चीन की डिजिटल कंपनियों के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर साझा मानक विकसित करना अब जी-7 की प्राथमिकताओं में शामिल है।

पांचवां, विश्व अर्थव्यवस्था की दिशा तय करना: जी-7 देश वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 29% हिस्सा रखते हैं। इसलिए ब्याज दरों, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाओं, ऊर्जा और वित्तीय स्थिरता से जुड़े इनके फैसलों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है।

छठा, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा: स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा पर लिए गए निर्णय विकासशील देशों की नीतियों को भी प्रभावित करते हैं।

जहां तक विभिन्न देशों पर इस शिखर बैठक के संभावित प्रभाव की बात है तो- अमेरिका: यूएस को वैश्विक नेतृत्व पुनर्स्थापित करने का अवसर मिलेगा। ईरान समझौते और यूक्रेन नीति पर समर्थन जुटाने की कोशिश रंग लाएगी। चीन के विरुद्ध आर्थिक गठबंधन मजबूत करने का प्रयास परवान चढ़ेगा।

चीन: चीन को जी-7 की आर्थिक और तकनीकी रणनीतियों से सबसे अधिक प्रभावित देश समझा जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों द्वारा वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाने की कोशिश चीन के निर्यात मॉडल को चुनौती दे सकती है।

रूस: रूस को नए प्रतिबंधों और यूक्रेन समर्थन के कारण दबाव बढ़ सकता है। रूस को चीन, ईरान और ग्लोबल साउथ देशों के साथ संबंध और मजबूत करने पड़ सकते हैं।

यूरोप: यूक्रेन और रूस मुद्दे पर यूरोप की सामूहिक रणनीति मजबूत होगी। ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा पर नया रोडमैप बन सकता है।

अरब-खाड़ी देश: ईरान-अमेरिका वार्ता और होर्मुज़ की स्थिरता से आर्थिक लाभ मिलेगा। ऊर्जा बाज़ार में अनिश्चितता कम हो सकती है।

भारत: भारत जी-7 का सदस्य नहीं है, लेकिन आमंत्रित भागीदार के रूप में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। लिहाजा भारत के लिए अवसर यह होगा कि पश्चिमी देशों की चाइना+1 नीति का सबसे बड़ा लाभार्थी बनने की संभावना है। इससे सेमीकंडक्टर, रक्षा, एआई और हरित ऊर्जा में निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। साथ ही अमेरिका, फ्रांस और यूरोप के साथ रणनीतिक साझेदारी गहरी हो सकती है। चूंकि भारत को अक्सर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इससे भारत को: वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में भागीदारी का अवसर मिलता है। तकनीक, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी मजबूत करने का मौका मिलता है। विकसित देशों के साथ रणनीतिक संबंध गहरे होते हैं।

जहां तक चुनौतियाँ और आलोचनाएँ सम्बन्धी बात है तो जी-7 की आलोचना भी होती है क्योंकि इसमें उभरती अर्थव्यवस्थाएँ (जैसे चीन) सदस्य नहीं हैं। कई विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व सीमित है। निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते। सदस्य देशों के बीच व्यापार, जलवायु और विदेश नीति को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं। निष्कर्ष: यह कहा जा सकता है कि जी-7 अब केवल अमीर देशों का क्लब नहीं है; बल्कि यह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, तकनीकी शासन, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। हालांकि इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि यह विकसित देशों के हितों से आगे बढ़कर व्यापक वैश्विक सहमति बना पाता है या नहीं।

आज का इतिहास

1576 अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दीघाटी का युद्ध शुरू हुआ।
1758 फ्रेंच जनरल बुस्सी ने निजाम सलाबत जंग से जाने की इजाजत ली, जो भारत से फ्रांस की मौजूदगी का अंत था।
1812 अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मेडिसन ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
1815 वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को हार का सामना करना पड़ा।
1858 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के निकट लड़ाई के मैदान में ब्रिटिश सेना से लोहा लेने के बाद मारी गईं।
1941 तुर्की ने नाजी जर्मनी के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1946 गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया।
1956 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ।
1972 ब्रिटिश यूरोपियन विमान 548 उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार 118 लोगों की मौत।
1979 अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियार नियंत्रण समझौता हुआ।
1987 एम एस स्वामीनाथन को पहला वर्ल्ड फूड प्राइज मिला।
2009 नासा ने चांद पर पानी की तलाश में विशेष यान भेजा।
1997 कंबोडिया के खमेर रूज के नेता और 20 लाख से ज़्यादा लोगों का हत्यारा माओवादी पोलपोट का आत्मसमर्पण।
1999 35 यूरोपीय देशों के बीच लंदन में पेयजल समझौते पर हस्ताक्षर, लातविया में वाइके फ़्रेबरेमा को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया।
2001 पाकिस्तान के रक्षा बजट में कटौती, तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के खिलाफ़ लादेन का फ़तवा रद्द किया।
2004 चाड के सैनिकों ने 69 सूडानी मिलिशियाई को मार गिराया। दक्षिण कोरिया ने अगस्त माह में ईराक में सेना भेजने का निर्णय लिया।
2008 केन्द्र सरकार ने गुर्जरों को ओबीसी कोटे में 5% आरक्षण देने की घोषणा की। भारत यात्रा पर आये सीरिया के राष्ट्रपति बशहर अल असद और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के मध्य तीन समझोते पर हस्ताक्षर हुए। फ़ार्मा कम्पनी रैनबैक्सी ने अमेरिका फ़ार्मा कम्पनी फ़ाइजर के साथ पेटेंट विवाद को एक समझौते के तहत समाप्त किया।
2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तान ने भारत को हरा कर खिताब जीता।

कांग्रेस को आंखे दिखाने वाली ममता के आंसूओं का मर्म

योगेंद्र योगी

राजनीति में नेता कब चौला बदल ले, पता नहीं चलता। कांग्रेस को आंखे दिखाने वाली पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब सोनिया गांधी से मिली उनकी आंखों में आंसू भर आए। यह वाक्या बताता है कि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं है। दोस्त कब दुश्मन बन जाएं और दुश्मन कब दोस्त, इसका राजनीतिक इतिहास पुराना है।

इंडिया गठबंधन की दिल्ली बैठक के दौरान सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की भावुक मुलाकात ने कांग्रेस-टीएमसी के 30 साल पुराने उतार-चढ़ाव वाले संबंधों और बंगाल चुनाव के बाद आयी दरारों को फिर से चर्चा में ला दिया। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी अपनी पार्टी में टूट के बीच जब बैठक में पहुंचीं, तो कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। बंद कमरे में अपनी पुरानी सहेली और राजनीतिक साथी को सामने देख ममता बनर्जी के आंसू छलक पड़े।

ममता के ये आंसू दरअसल कांग्रेस के साथ किए गए अपने खराब पुराने बर्ताव या कांग्रेस से अलग होने की गलती के एहसास की वजह से नहीं आए, बल्कि भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव जीत कर सारा दंभ हवा होने से गई सत्ता गंवाने और अपने सांसदों के टूटने की वजह से आएं। दरअसल पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने और पार्टी के सांसदों के विद्रोह से ममता के राजनीतिक अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। जिसकी ममता बनर्जी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी।

ममता को सोनिया गांधी से मिली 'जादू की झप्पी' सिर्फ व्यक्तिगत ढाढ़स नहीं थी। यह कांग्रेस और टीएमसी के बीच पिछले 3 दशकों से चले आ रहे उतार-चढ़ाव, पुरानी राजनीतिक दरारों और बंगाल में एक-दूसरे के वजूद को मिटाने की खूनी क्रोनोलॉजी का अंतिम और सबसे असहाय पड़ाव था। 1997-98 में ममता बनर्जी ने तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व (सोनिया गांधी के उभार के समय) पर वामपंथियों (वाममोर्चा) के खिलाफ ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था।

ममता ने अलग तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। अगले दो दशक में ममता बनर्जी ने वामपंथ के साथ-साथ कांग्रेस को भी

बंगाल में शून्य कर दिया। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस को महज दो सीटों पर ही लोकसभा चुनाव लड़ने की पेशकस की थी, मगर कांग्रेस टीएमसी से 10-12 सीटों की डिमांड कर रही थी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की 10-12 लोकसभा सीटों की मांग को 'अनुचित' बताया था और पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे पर चर्चा में देरी के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी।

ममता ने 'एकला चलो' की नीति अपनाते हुए बहरमपुर में यूसुफ पठान को उतारकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया। इससे दिल्ली का कांग्रेस नेतृत्व अंदर से बेहद आहत था। कांग्रेस पार्टी के पारंपरिक गढ़ों (मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर) को भी पूरी तरह से ममता बनर्जी ने निगल लिया। अधीर रंजन चौधरी जैसे कद्दावर नेताओं को साइडलाइन कर उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक पर अपना एकछत्र राज स्थापित कर लिया था।

ममता की राजनीतिक महत्वकांक्षा इतनी प्रबल हो गई, कि पश्चिम बंगाल तक सीमित होने के बावजूद कांग्रेस का नेतृत्व किसी रूप में स्वीकार करने से इंकार कर दिया। इससे भी आगे बढ़ कर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व का दावा तक पेश कर दिया था। इस नेतृत्व का मतलब था गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद की दावेदारी। ममता बनर्जी ने चुनावों और उपचुनावों में इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन पर निराशा जाहिर करते हुए कहा था कि वह इसकी कमान संभालने को तैयार है।

कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने तब कहा था कि %ममता बनर्जी को ऐसा लगता है पर हमें ऐसा नहीं लगता। चर्चा करेंगे। उनके कहने से उनकी पार्टी चलती है। हम तो कांग्रेस के कहने से चलते हैं। केरल में वाम शासन को काग्रेस के हाथ गंवा चुकी लेफ्ट ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए थे। तब लेफ्ट नेता डी राजा ने भी कहा था कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। राज्या ने कहा था कि कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में गठबंधन सहयोगियों को समायोजित नहीं किया। अगर कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक सहयोगियों की बात सुनी होती तो लोकसभा और हरियाणा-महाराष्ट्र में नतीजे अलग होते।

बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटें जीतकर ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर दिया, तो अचानक से पूरी बाजी पलट गयी। सत्ता हाथ से जाते ही टीएमसी के भीतर सांसदों और विधायकों में भगदड़ मच गयी। टीएमसी से बगावत करने वाले सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिख कर अलग से सीट देने की मांग की है। इससे पहले टीएमसी के विधायक पश्चिम बंगाल विधानसभा मे यह कारनामा कर चुके हैं। इसके बाद ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की याद आयी। गठबंधन की बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख बचाने के लिए दीदी अब कांग्रेस और सोनिया गांधी के दरबार में मदद की गुहार लगा रही हैं।

देश की सबसे कद्दावर विपक्षी चेहरा रहीं ममता बनर्जी की हकीकत अब यही है कि 'इंडिया' गठबंधन में 'किंगमेकर' या प्रधानमंत्री पद की दावेदार वाली उनकी पुरानी मजबूत स्थिति अब नहीं रही। इसलिए वह इंडिया गठबंधन की शरण में हैं। कांग्रेस बेशक लोकसभा और ज्यादातर राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा को टक्कर नहीं दे सकी, किन्तु गठबंधन में कांग्रेस का दबदबा है, इसलिए ममता को लगता है कि सहानुभूति पाकर कांग्रेस से डूबते को तिनका का सहारा मिल सकता है।

राजनीतिक में जमीर को एक तरफ करके सत्ता के लिए नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। दरअसल नेताओं में नैतिकता या सिद्धान्त बचा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सत्ता की राजनीतिक में आवरण बदलने का काम सिर्फ ममता ने ही किया हो, इससे पहले भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने दूसरे दलों से गठबंधन करके और मौका पाकर उनको छिटक कर यह काम किया है।

प्रतिरोध की राजनीति ने गढ़ी ईरान की नई छवि

देवेश त्रिपाठी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और ईरान को निशाना बनाने वाली अमेरिकी कार्रवाइयों को कई लोग एक चेतावनी के रूप में देख रहे हैं- एक ऐसी हिंसक सजा, जो किसी भी अव्यवस्थित देश को मिल सकती है। आलम यह है कि वे देश भी, जो ईरानी सरकार की घरेलू नीतियों या क्षेत्रीय गतिविधियों से सहमत नहीं हैं, कई मामलों में 'जे सुई ईरान' (मैं भी ईरान हूं) जैसी भावना को महसूस कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि अमेरिका और इस्त्राइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध ऐसे समय में छेड़ा, जब दुनिया खुद को फिर से व्यवस्थित कर रही थी और कई देश खुद को डोनाल्ड ट्रंप की 'लेन-देन' आधारित तथा दबावपूर्ण विदेश नीति के अनुरूप ढालने का दबाव महसूस कर रहे थे।

अपनी संप्रभुता और रणनीतिक स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए छोटे और मध्यम दर्जे के देश अब नए विकल्पों की तलाश में हैं। कई राष्ट्र अमेरिका पर निर्भरता कम करते हुए चीन व अन्य ताकतों के साथ अपने व्यापार और संबंध बढ़ा रहे हैं। ऐसे माहौल में ईरान के खिलाफ युद्ध तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था का एक निर्णायक मोड़ बनकर उभरा है। ईरान ने न केवल यह दिखाया है कि वह वैश्विक समुद्री व्यापार के एक अहम रास्ते (चोकपॉइंट) को प्रभावित करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की क्षमता रखता है, बल्कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों के हवाई हमलों का बखूबी सामना भी कर सकता है। शायद यही कारण है कि कभी वैश्विक व्यवस्था के हाशिये पर धकेला गया, प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय अलगाव से घिरा ईरान आज दुनिया के कई हिस्सों में प्रतिरोध, आत्मसम्मान और दबाव के सामने न झुकने वाली राजनीतिक इच्छाशक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने ईरान के नेतृत्व को क्यूबा, लीबिया, उत्तर कोरिया और निकारागुआ के शासकों की श्रेणी में रखते हुए उन्हें गैर-जिम्मेदार, सनकी और आपराधिक प्रवृत्ति वाले नेता करार दिया। इतना ही नहीं, 2000 के दशक के आखिर तक, जॉन मैक्केन और हिलेरी क्लिंटन ने ईरान पर बम गिराने की हिंसक धमकियों को अमेरिका की विदेश नीति की आम बातचीत बना दिया।

खोमैनी के बाद सर्वोच्च नेता बने अयातुल्ला अली खामनेई ने भी अमेरिका के प्रति वही कठोर और गुस्से भरी भाषा का सिलसिला जारी रखा। अपनी मृत्यु से महज ग्यारह दिन पहले 86 वर्षीय खामनेई ने अमेरिका को 'पतन की ओर बढ़ता हुआ साम्राज्य' करार दिया था। आज जब ईरान दुनिया की ओर देखता है, तो उसे कई देशों में इसी तरह की असंतुष्टि और संदेह की भावना दिखाई देती है। हालांकि, पश्चिम एशिया में चीन और रूस के हित एक जैसे नहीं हैं। चीन अपने आर्थिक निवेश और तेल की स्थिर कीमतों को लेकर चिंतित रहता है, जबकि रूस की सोच अलग है। फिर भी, दोनों ने स्वयं को ऐसी शक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया है, जो युद्ध और बाहरी दबाव से प्रभावित देशों तथा क्षेत्रीय समूहों के साथ संबंध मजबूत करने को तैयार हैं। हालांकि, कई देश ऐसे भी रहे, जिन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर कोई पक्ष लेने के बजाय चुप रहना ही बेहतर समझा। शायद इसलिए, क्योंकि वे नहीं जानते कि भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों या दबाव का अगला निशाना कौन-सा देश बन सकता है।

कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं हैं कि ईरान द्वारा अमेरिका का सफलतापूर्वक विरोध करने से अमेरिका का प्रभाव कम हो जाएगा। आखिर, अमेरिका की सैन्य हार कोई नई बात नहीं है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से अमेरिका के ज्यादातर सैन्य दखल-वियतनाम, कोरिया, अफगानिस्तान और इराक-ऐसे लंबे खिंचने वाले और कम तीव्रता वाले संघर्षों में बदले, जिन्हें शायद ही कोई जीत कह सकता है। लेकिन, यह तय है कि ट्रंप और इस्त्राइल ने मिलकर ईरान की सरकार को और मजबूत किया है।

सार्वजनिक जीवन में विश्वास की पूंजी

डॉ. आशीष वशिष्ठ

विश्वास और भरोसा ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। सार्वजनिक जीवन में जन विश्वास गंवाने वाला व्यक्ति किसी योग्य नहीं रह जाता। हाल ही में भारतीय राजनीति में जन विश्वास से जुड़ी दो अहम घटनाएं घटित हुई। पहली घटना में एक नेता ने जन विश्वास की पूंजी खो दिया। वहीं दूसरी घटना में नेता ने जन विश्वास की पूंजी को सहेजा ही नहीं, बल्कि हर बीतते दिन के साथ उसमें वृद्धि भी की।

पहली घटना 4 मई की है। इस दिन जन विश्वास खो चुकी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तृणमूल और ममता से नाराजगी का आलम यह था कि स्वयं ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई। आज ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की जो दुर्दशा हो रही है, उसकी जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं बल्कि वह स्वयं और उनके कर्म ही हैं।

तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसद अपना अलग गुट बना चुके हैं। स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है, जब किसी राजनीतिक दल का इतनी तेजी से विघटन हुआ हो। या किसी नेता की तथाकथित साख चुनाव हारने के चंद दिनों में ही औंधे मुंह गिरी हो। सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी को मंदिर जाने की याद आई। कालीबाड़ी दर्शन करने पहुंची ममता बनर्जी को लोगों ने पूरी तरह अनदेखा किया। डेढ दशक तक सूबे का मुख्यमंत्री रहने वाले नेता की जनता इस हद तक उपेक्षा करे, तो यह सिर्फ चुनावी हार नहीं, जनविश्वास के टूटने का संकेत होता है।

तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से आजिज जनता आज उसके नेताओं का अंडे, टमाटर, जूते और मार कुटाई से सत्कार कर रही है। तृणमूल के नेताओं को देखकर चोर-चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। ये वो लोग है जो पिछले 15 वर्षों से तृणमूल नेताओं की तानाशाही, गुण्डागर्दी और अत्याचार चुपचाप सह रहे थे। तृणमूल नेताओं के प्रति जनता का व्यवहार उनके स्वाभाविक क्रोध, कुंठा, निराशा और हताशा का परिणाम है।

ममता सरकार के डेढ़ दशक के शासन के दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं की हत्या व अपहरण, पोलिंग एजेंटों की पिटाई, बमबाजी, गोलीबारी, बूथों में तोड़फोड़, वोटों की लूट, प्रत्याशियों व उनके परिवार के सदस्यों को धमकियां, ये सब बंगाल में आम बातें हो चुकीं थीं। भाजपा के अपने अनुमानों के अनुसार,

2021 में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हुई हिंसा में टीएमसी के गुंडों ने 300 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की थी। तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कानून व व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि, राज्य में लोकतंत्र सांस नहीं ले पा रहा है। मुख्यमंत्री और प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं।

दूसरी घटना 10 जून को घटित हुई। इस दिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन पूरे किए, जो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में पूरे किए गए 4,398 दिन के कार्यकाल से ज्यादा है। इस तरह जनविश्वास, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। यह सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, 140 करोड़ भारतीयों के अटूट विश्वास की जीत है।

2014 में देश ने उत्साह और अटूट विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन उन्होंने स्वयं को हमेशा एक प्रधानसेवक माना। इसी रूप में वे अपना राष्ट्रधर्म निभाते हुए विकसित भारत के निर्माण में जुटे हैं। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के संकल्प के साथ उन्होंने समाज के हर वर्ग का विश्वास जीता है। उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अधिकार, सम्मान और आत्मनिर्भरता का एहसास कराया है। विपक्ष के लगातार मिथ्या प्रचार, व्यक्तिगत हमलों, यहां तक की अपशब्द देने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी अहर्निशं जनसेवा में जुटे हैं। देश की जनता उन पर भरोसा करती है, जनता को विश्वास है मोदी के रहते उनका अहित नहीं होगा। इसलिए वो लगातार तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी सहर्ष सौंपती है।

जब विश्वास टूटता है तो बड़े से बड़े नेता और व्यक्ति अर्श से फर्श पर आ जाता है। भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी का बड़ा कद था। लेकिन अपनी सत्ता बचाने के लिए 1975 को इमरजेंसी लगाने के बाद जनता का विश्वास इंदिरा गांधी से टूट गया। 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस को ऐतिहासिक हार का मुंह देखना पड़ा और देश में आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ।

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, उड़ीसा में बीजू जनता दल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी तमाम ऐसे उदाहरण ऐसे हैं, जब जनता ने इन दलों पर विश्वास करके सत्ता के सिंहासन पर बैठाया। लेकिन जब ये नेता विश्वास और उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो, जनता ने इन्हें इनको आसमान से जमीन पर पटकने में देरी नहीं की। तमिलनाडु में विश्वास ही तो खत्म हुआ होगा, तभी तो वहां की जनता ने सत्तारूढ़ डीएमके को हटाकर अभिनेता चंद्रशेखरन जोसेफ विजय की नयी नवेली पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके को सत्ता की कुंजी सौंप दी।

वहीं कई ऐसे उदाहरण भी हैं, जहां विश्वास के चलते जनता ने बार बार जीत का आशीष दिया। गुजरात में बीते 31 और मध्य प्रदेश 21 साल से भाजपा की सरकार है। इतने लंबे समय तक विश्वास और सेवा किये बिना कोई नेता या दल सत्ता या लोगों के दिलों में नहीं रह सकता। किसी जमाने में हरियाणा में भाजपा कोई बड़ी शक्ति नहीं थी। बामुश्किल उसके दो या तीन विधायक ही जीतते थे। लेकिन विश्वास और जनसेवा की बदौलत ही पिछले 12 वर्षों से हरियाणा में भाजपा की सरकार सत्ता में है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मिथक था कि यहां कोई सरकार दोबारा रिपीट नहीं करती। 2017 में भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कृतित्व एवं व्यक्तित्व से सरकार और शासन के प्रति जनता के विश्वास को लगातार बढ़ाने का काम किया। नतीजा उत्तर प्रदेश की राजनीति में 37 साल पुराना यह मिथक 2022 के विधानसभा चुनाव में टूट गया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भाजपा सरकार पिछले नौ साल से लगातार जनसेवा में जुटी है।

जीवन की सबसे बड़ी पूंजी पद नहीं, बल्कि विश्वास होता है। यह विश्वास किसी नेता, राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। यह विश्वास बना रहना ही चाहिए। और जिस दिन यह विश्वास टूटता है, उस दिन नतीजे वैसे ही होते हैं, जैसे 4 मई को पश्चिम बंगाल में ईवीएम से निकले। हारने वाला कुंठा, निराशा और हताशा में भले ही इसे वोट की लूट बताता रहे, लेकिन ये वोट की नहीं बल्कि दिल की लूट होती है। इसलिए व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में विश्वास बनाए रखें।

राजनीति में स्थाई मित्र या शत्रु जैसी कोई चीज नहीं होती

विनोद पाठक

राजनीति में स्थाई मित्र या स्थाई शत्रु जैसी कोई चीज नहीं होती। यहां परिस्थितियां, जनमत और सत्ता का समीकरण इतनी तेजी से बदलते हैं कि कल तक अजेय दिखने वाला राजनीतिक दल भी कुछ समय बाद अस्तित्व के संकट से जूझता नजर आ सकता है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में हाल के दिनों में आया अभूतपूर्व घटनाक्रम इसी अनिश्चितता की एक बड़ी मिसाल बनकर सामने आया है। चुनावी परिणामों के बाद जिस तेजी से तृणमूल कांग्रेस का संसदीय ढांचा दरका और उसके कई सांसदों ने एक नए राजनीतिक मंच का रुख किया, उसने केवल पश्चिम बंगाल की राजनीति को ही नहीं झकझोरा, बल्कि देश में दलबदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता और उसकी सीमाओं पर भी नए सिरे से बहस छेड़ दी है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निर्वाचित प्रतिनिधियों के सामूहिक रूप से दल बदल लेने को केवल कानूनी प्रक्रिया मान लिया जाए या इसके नैतिक पहलुओं पर भी गंभीर चर्चा होनी चाहिए? आखिर जनता ने वोट किसी व्यक्ति को दिया था, किसी विचारधारा को या उस राजनीतिक दल को जिसके प्रतीक और नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ा गया था?

पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक चर्चा उस नई राजनीतिक इकाई %नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया% की हो रही है, जिसके बारे में आम राजनीतिक विमर्श में पहले बहुत कम जानकारी थी। पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी 14 जून को सक्रिय हुए हैं, जिन पर तृणमूल कांग्रेस से आए सांसदों का स्वागत किया गया है। ये सांसद अब मोदी सरकार को बाहर से सशर्त समर्थन देंगे।

इन सांसदों में कई सांसद तो ऐसे हैं, जो पानी पी-पीकर रोज भाजपा नेतृत्व को कोसते थे। अचानक इस मंच पर कई सांसदों का एक साथ आ जाना स्वाभाविक रूप से अनेक सवाल खड़े करता है। क्या यह वास्तव में एक नई राजनीतिक विचारधारा की शुरुआत है या फिर केवल दलबदल विरोधी कानून की सीमाओं के भीतर रहते हुए

राजनीतिक अस्तित्व बचाने की एक रणनीति?

क्या जनता ऐसे नए राजनीतिक प्रयोग को स्वीकार करेगी या इसे केवल सत्ता की बदलती दिशा के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश के रूप में देखेगी?

भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि केवल नेताओं का समूह किसी दल को जनाधार नहीं दिला सकता। किसी राजनीतिक दल की वास्तविक शक्ति उसके कार्यकर्ताओं, संगठन, विचार और जनता से उसके संबंधों में निहित होती है। यही कारण है कि कई बड़े राजनीतिक प्रयोग शुरुआत में चर्चा का विषय तो बने, लेकिन समय की कसौटी पर टिक नहीं सके।

भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे दलबदल विरोधी कानून कहा जाता है, 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू की गई थी। इसका उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता और अवसरवादी दलबदल पर रोक लगाना था। बाद में 91वें संविधान संशोधन के जरिए यह व्यवस्था की गई कि यदि किसी विधायी दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी दूसरे दल में विलय का निर्णय लेते हैं तो उसे दलबदल नहीं माना जाएगा और उनकी सदस्यता सुरक्षित रह सकती है।

यही वह कानूनी प्रावधान है, जो ऐसे मामलों में सबसे अधिक विवाद का कारण बनता है। कानून यह अनुमति देता है, लेकिन क्या यह व्यवस्था मतदाता की मूल भावना के अनुरूप है? क्या दो-तिहाई सदस्यों के एक साथ चले जाने से जनता का जनादेश भी स्वत: स्थानांतरित माना जा सकता है? शायद यही वह प्रश्न है जिस पर भविष्य में संसद और न्यायपालिका दोनों को व्यापक विमर्श करना पड़ सकता है।

भारतीय राजनीति में गोवा, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के कई उदाहरण बताते हैं कि बड़े राजनीतिक दल भी टूटे हैं और नए राजनीतिक समीकरण बने हैं, लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि राजनीति में कोई भी शून्य हमेशा के लिए नहीं रहता। पश्चिम बंगाल ने पिछले पांच दशकों में कई बड़े परिवर्तन देखे हैं। कभी कांग्रेस प्रमुख शक्ति थी, फिर वामपंथ का लंबा दौर आया, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का उदय हुआ। यह इतिहास संकेत देता है कि जनता अंतत: नए विकल्प भी तैयार कर सकती है।

इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष की राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। हालांकि, यह जरूर कहा जा सकता है कि यदि तृणमूल कांग्रेस अपने संगठन और जनाधार को पुनर्जीवित नहीं कर पाती तो राज्य की राजनीति में एक बड़ा रिक्त स्थान पैदा हो सकता है, जिसे भरने के लिए नई राजनीतिक शक्तियां सामने आएंगी।

पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र के सामने एक मूल प्रश्न खड़ा कर दिया है, क्या दलबदल विरोधी कानून का वर्तमान स्वरूप जनता की राजनीतिक इच्छाओं की पूरी तरह रक्षा कर पा रहा है? कानूनी रूप से दो-तिहाई सदस्यों का विलय वैध माना जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं चलता, बल्कि जनता के विश्वास और राजनीतिक नैतिकता से भी संचालित होता है।

पश्चिम बंगाल में जो कुछ घटित हुआ है, उसका वास्तविक फैसला न केवल विधानसभा या संसद के भीतर होगा, बल्कि आने वाले चुनावों में जनता के बीच भी होगा। जनता यह तय करेगी कि यह परिवर्तन राजनीतिक आवश्यकता था, अवसरवाद था या फिर राज्य की राजनीति में किसी नए अध्याय की शुरुआत।

पश्चिम बंगाल का यह राजनीतिक भूचाल केवल एक दल के टूटने या नए दल के बनने की कहानी नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र के उस जटिल प्रश्न की ओर संकेत करता है, जहां कानून और नैतिकता कई बार एक-दूसरे के समानांतर खड़े दिखाई देते हैं।

भारत को ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीति पर करना होगा पुनर्विचार

केएस तोमर

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने से सबसे बड़ा लाभ अगर किसी प्रमुख देश को मिल सकता है, तो वह भारत है। पूरे संकट के दौरान नई दिल्ली ने सावधानीपूर्वक सभी पक्षों के साथ अपने संबंध बनाए रखे और समझौते का स्वागत किया। इस शांति समझौते को पश्चिम एशिया में स्थिरता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि, इस टकराव ने पश्चिमी एशिया को लेकर भारत की कमजोरी को भी उजागर किया। देश के कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी की जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। जैसे-जैसे तनाव बढ़ा, भारतीय रिफाइनरियों को वैकल्पिक और महंगे आपूर्ति स्रोतों की तलाश करनी पड़ी। भले ही युद्धविराम ने फिलहाल चिंताओं को कम कर दिया हो, पर इस संकट ने नीति-निर्माताओं को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना और रणनीतिक भंडार को मजबूत करना अब समय की मांग है। इस शांति समझौते से ईरान के साथ भारत के गहरे जुड़ाव की संभावनाएं फिर से बन सकती हैं। हालात सामान्य होने पर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के नए अवसर खुल सकते हैं। साथ ही, चाबहार बंदरगाह परियोजना को भी नई गति मिलने की संभावना है। यह परियोजना भारत की उस रणनीतिक योजना का अहम हिस्सा है, जिसके जरिये वह मध्य एशिया और उससे आगे के बाजारों तक अपनी पहुंच मजबूत करना चाहता है। नई दिल्ली के लिए इस संकट से मिलने वाला बड़ा सबक आर्थिक नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक है। टकराव के दौरान, भारत ने सीधे तौर पर इसमें शामिल हुए बिना अमेरिका, इस्त्राइल व ईरान और अरब जगत के साथ अपने संबंधों में प्रभावी संतुलन बनाए रखा। वाशिंगटन और तेहरान का बातचीत की मेज पर लौटना यह दिखाता है कि जब टकराव की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है, तो बड़ी ताकतों को भी अक्सर कूटनीति का रास्ता चुनना पड़ता है। भारत के लिए इससे मिलने वाले संदेश बिल्कुल स्पष्ट हैं कि वह रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखे, सभी प्रमुख शक्तियों के साथ आत्मविश्वास के साथ संवाद जारी रखे और किसी एक शक्ति-गुट के साथ पूरी तरह जुड़ने के बजाय व्यावहारिक कूटनीति के जरिये अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे। भारत के दृष्टिकोण से देखें, तो पश्चिमी एशिया में शांति निस्संदेह उसके लिए फायदेमंद है। खाड़ी क्षेत्र में किसी भी टकराव का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, महंगाई के स्तर, व्यापार संतुलन और आर्थिक विकास पर पड़ता है। युद्धविराम से वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता कम होगी और लंबे समय तक ऊर्जा संकट का जोखिम भी घटेगा। इससे उन भारतीयों को भी फायदा मिलेगा, जो खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। तनाव के दौरान यह चिंता बनी हुई थी कि यदि संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैलता है, तो रोजगार और प्रवासी भारतीयों की कमाई प्रभावित हो सकती है। शांति से ये जोखिम काफी हद तक कम हो जाते हैं और लाखों भारतीय परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। समुद्री व्यापार मार्गों के सामान्य होने और व्यावसायिक गतिविधियों के रफ्तार पकड़ने से भारतीय व्यापार को भी बड़ा लाभ मिलेगा। संकट के दौरान ईरान व इस्त्राइल के प्रति भारत के संतुलित नजरिये की भी पुष्टि हुई है। सभी पक्षों के साथ संवाद बनाए रखकर भारत ने न केवल रणनीतिक लचीलेपन को बनाए रखा, बल्कि खुद को एक महंगे क्षेत्रीय टकराव में उलझने से भी बचाया। हालांकि, शांति समझौते की कूटनीतिक प्रक्रिया में भारत की सीमित भूमिका पर भी सवाल उठे हैं।

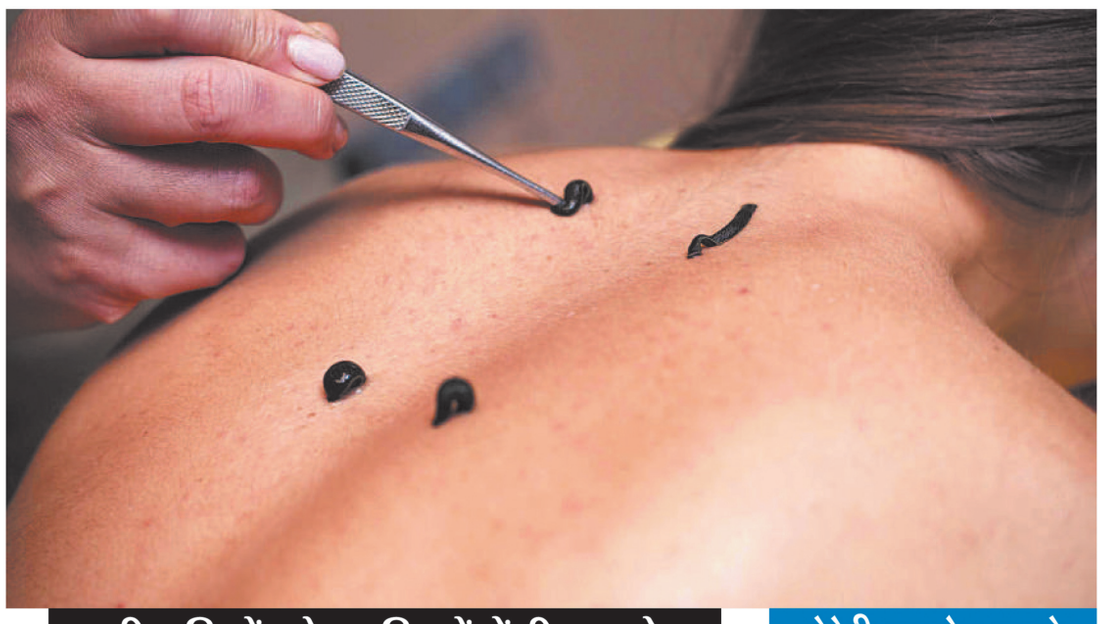

बीमारियों को चुटकियों में ठीक करे

जोंक थेरेपी

लीच थेरेपी यानि जोंक चिकित्सा को प्राचीन काल से ही इस्तेमाल किया जाता है। उन्नीसवीं सदी की शुरूआत में यह थेरेपी उच्चतम लोकप्रियता पर पहुंच गई थी। लेकिन बींसवी सदी में लोगों के बीच इसका क्रेज नहीं रहा। आधुनिक विज्ञान ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और तर्क के आधार पर चिकित्सा करनी शुरू की दी। लेकिन हाल ही में कुछ शोधकर्ताओं ने पाया यह चिकित्सा पद्धति काफी स्वास्थ्यकारी है।

इस उपचार विधि को हिरदुथेरेपी के नाम से जाना जाता है। लीच थेरेपी को हृदय रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। लीच यानि जोंको के द्वारा निकलने वाली लार से शरीर का रक्त पतला होता है और रक्त का थक्का नहीं जमता है। यह शरीर में रक्त का संचार अच्छा कर देता है और संयोजी ऊतकों में दर्द के लिए संवेदनशीलता को बढ़ाता है। वैकल्पिक चिकित्सा की समीक्षा में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जोंक चिकित्सा, सूजन और पैर दर्द में भी लाभकारी होती है और त्वचा के मलिनकरण को भी कम कर देती है। अगर पैरों में गहरी नसों में रक्त का थक्का जम जाता है तो इससे सही हो जाता है। बस, प्रभावित हिस्से में चार से पांच जोंक को चिपका दिया जाता है और उन्हें काटने दिया जाता है।

बहुत सारे चिकित्सकों का मानना है कि लीच थेरेपी, सर्जरी के बाद टिश्यू को हेल्दी बनाएं रखने के लिए भी अच्छी रहती है। जोंक की लार की मदद से रक्त पतला बना रहता है और शिराओं में घनापन नहीं हो पाता है।

थेरेपी उपयोग करने के फायदे

- दर्दनाक चोटों और पुनर्निर्माण सर्जरी के फलस्वरूप होने वाली सूजन में भी यह थेरेपी कारगर होती है। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि यह कैंसर ड्रग के रूप में भी उपयोगी हो सकती है।
- लीच यानि जोंक की लार में घिलाटेन नामक घटक पाया जाता है जो विभिन्न प्रकार के ट्यूमर की ग्रोथ को रोक देता है। साथ ही इसकी लार में पेप्टाइड भी होता है जिसे हीरूडिन कहा जाता है जो काफी बेहतर एंटीकोग्लुएंट होता है और इसमें कैंसर-विरोधी गुण भी होते हैं। अचानक से होने वाले बहरेपन, सूजन और टिटनेस में भी यह लाभकारी होती है।
- अनुसंधान आयुर्वेद लेख के अनुसार, जब लीच थेरेपी को रोगी की टांग पर शुरू किया जाता है जो गठिया की समस्या में उसे काफी लाभ मिलता है। हालांकि, इसे बेहद सावधानी से करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके काफी साइडइफेक्ट भी होते हैं। इससे त्वचा पर दाग पड़ सकता है, फफोले पड़ सकते हैं और वहां पर घाव भी हो सकता है।

फोल्डेबल स्मार्ट इलेक्ट्रिक बाइक...

चीन की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी शाओमी ने नई फोल्डेबल स्मार्ट इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की है जिसकी कीमत 2,999 युआन यानी करीब 30,699 रुपए है। बाइक में इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो टार्क मेजरमेंट मेथड से राइडर को बाइक चलाने में मदद करती है। यह बाइक फिटनेस से संबंधित मानकों को भी जैसे कैलोरीज बर्नड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और स्पीड के बारे में भी बताती है। इसमें पैनासोनिक की 18650 बैटरी लगाई गई है जो एक बार चार्ज करने पर 45 किलोमीटर का बैकअप देती है। इसके डिजाइन को इस तरह बनाया गया है कि आप आसानी से फोल्ड कर इसे कहीं भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं।

ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया क्या है ?

ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया (ओएसए) नामक रोग में सोते समय अक्सर सांस लेने की प्रक्रिया कुछ पलों के लिए रुक जाती है और इसके बाद यह फिर शुरू हो जाती है।

लक्षण

- इतनी जोर से खर्राटे लेना कि अन्य लोगों की नींद में खलल पड़े।
- सोते हुए बीच-बीच में अचानक सांस नहीं आना, जिससे अक्सर पीड़ित व्यक्ति नींद से उठ जाता है।
- सोते समय बीच-बीच में सांस रुकना।
- दिन भर सुस्ती छाई रहना, जिससे व्यक्ति काम के दौरान, टेलीविजन देखते हुए या वाहन चलाते हुए सो सकता है।

किन लोगों को है जोखिम

- मोटापे से ग्रस्त लोगों को ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया होनी की आशंकाएं ज्यादा होती हैं।
- गर्दन के मोटा होने से सांस मार्ग छोटा हो सकता है और यह स्थिति मोटापे का संकेत हो सकती है। पुरुषों के लिए गर्दन की माप 17 इंच और महिलाओं के लिए 16 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक होने पर ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया का जोखिम बढ़ जाता है।
- ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया होने की संभावना उन लोगों में दोगुनी हो जाती है, जिन्हें रात में अक्सर नाक बंद होने की समस्या रहती है।

जटिलताएं

इलाज न होने पर ओएसए से कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

कार्डियो-वैस्क्युलर समस्याएं

ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया के दौरान रक्त के ऑक्सीजन स्तर में अचानक कमी आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना और कार्डियो-वैस्क्युलर सिस्टम पर दबाव बढ़ना सरीखी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इस रोग से ग्रस्त कई लोगों में उच्च रक्तचाप की समस्या होती है, जिससे हृदय संबंधी रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया जितना गंभीर होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दिल का दौरा पड़ना, हृदय की धड़कन रुक जाना और स्ट्रोक होने का जोखिम उतना ही बढ़ जाता है।

- दूसरों की नींद पूरी नहीं होना- तेज खर्राटों के कारण आपके आसपास के लोगों को भी सही तरीके से आराम नहीं मिल पाता। इसका असर आपके संबंधों पर भी पड़ने लगता है।

जांच

स्लीप स्टडी या पॉलीसोम्नोग्राफी की जाती है। इसके अंतर्गत पल्स ऑक्सीमेट्री (ऑक्सीजन), मस्तिष्क की तरंगें (ईईजी), दिल की धड़कन (ईकेजी), सीने और आंखों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है।

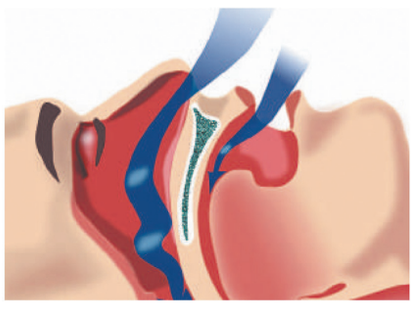

आधुनिक जांच प्रक्रिया

आधुनिक तकनीक की मदद से आप इस रोग से संबंधित परीक्षणों को अपने घर में करा सकते हैं ताकि आपको अस्पताल में रात बिताने की जरूरत न पड़े। घड़ी की तरह दिखने वाली इस डिवाइस को आपकी उंगलियों के पौरों और बाजुओं पर लगा दिया जाता है, जिससे आपकी सोने की स्थितियों और आंखों की हरकतों पर नजर रखी जा सके।

निद्रा अध्ययन भी जरुरी

निद्रा-अध्ययन के माध्यम से आपकी निद्रा संबंधी समस्याओं की जांच की जाती है। यह निद्रा के दौरान आपके मस्तिश्क की गतिविधियों, हृदय गति, पांवों के संचलन, ऑक्सीजन के स्तर तथा श्वास-संचालन की 6 से 8 तक घंटे की रिकॉर्डिंग होती है।

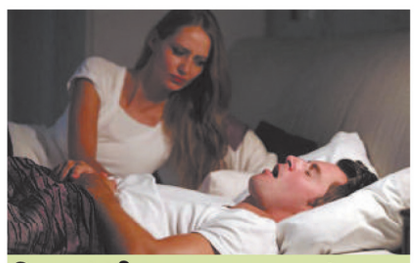

निद्रा संबंधी सामान्य समस्याएं

- नींद आने में कठिनाई/समय लगना
- स्लीप एप्निआ जिसमें नींद के दौरान कभी-कभी साँस बंद हो जाती है
- खर्राटे लेना
- दिन में उनींदा लगना
- चीखते हुए, संभ्रम (कंफ्यूजन) अथवा घबराहट के साथ जागना यदि आपके अध्ययन से पता चलता है कि आप निद्रा संबंधी किसी अव्यवस्था के शिकार हैं तो आपके लिए सर्वश्रेश्ठ इलाज चुना जा सके, इसके लिए आपको एक और रात वापस आना होगा।

इलाज

- निरंतर हवा का सकारात्मक दबाव बने रहना (सीपीएपी): यह एक छोटा पोर्टेबल मैकेनिकल डिवाइस है। इस डिवाइस में एक पंखा लगा होता है, जो नींद के दौरान लगातार हवा देकर आपके सांस मार्ग को खुला रखता है।
- कुछ ऐसे प्लास्टिक डिवाइस होते हैं, जिन्हें मुंह में पहना जाता है। दिखने में ये ऑर्थोडॉन्टिक रिटेनर्स या स्पोर्ट माउथ गार्ड्स की ही तरह होते हैं। ये ओरल डिवाइस सांस मार्ग को चिपकने से रोकते हैं।
- सर्जिकल इलाज के अंतर्गत नाक, तालू, जीभ, जबड़ा, गर्दन और कई अन्य जगहों की समस्याओं को दूर किया जाता है। सबसे लोकप्रिय सर्जरी लेजर प्रक्रिया है, जो खर्राटे भरने और सोते वक्त सांस की समस्या को दूर करने में सक्षम हैं।

कान छिदवाने के इन फायदों के बारे में पता है आपको ?

कान छिदवाना ना मात्र फैशन की देन है बल्कि यह भारतीय संस्कार का एक अहम हिस्सा भी है। जहां लड़कियां कान और नाक दोनों ही छिदवाती हैं वहीं आज कल तो पुरुष भी फैशन के चक्कर में एक कान या दोनों कान छिदवाने से पीछे नहीं हटते।

कान छिदवाने के बाद देखभाल करने के खास टिप्स: भारत के अनेक राज्यों में आज भी कर्णवेध संस्कार होता है जिसमें बालक और बालिकाओं का कान छेदा जाता है। अन्य संस्कारों की भांति इसे भी आवश्यक माना जाता था। कान छिदवाने की प्रथा कोई ऐसे ही नहीं शुरु की गई थी, बल्कि इसके पीछे कई स्वास्थ्य लाभ भी छुपे हुए थे।

कान छिदवाना समय ध्यान रखें ये बातें : कान के बीच की सबसे खास जगह पर जब प्रेशर लगाया जाता है तो इसके बीच की सभी नसें एक्टिव हो जाती हैं। आज हम मात्र फैशन को ध्यान में रख कर कान छिदवाते हैं मगर जब आप इसके स्वास्थ्य लाभो के बारे में पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे।

दिमाग का विकास होता है: महान ऋषि सुश्रुत के अनुसार कान के निचले हिस्से (ear lobes) में एक प्वाइंट होता है, जो मस्तिष्क के बाएं और दाएं गोलार्द्ध से कनेक्ट होते हैं। जब इस प्वाइंट पर छेद किए जाते हैं तो, यह दिमाग के हिस्से को एक्टिव बनाते हैं। इसलिए जब बच्चे का दिमाग बढ रहा हो, तभी उसके कान छिदवा देने चाहिए।

हार्ट अटैक को अब मात देगा पीपल

पीपल का पेड़ यानी भूतों का घर, ऐसा हमारा कहना नहीं लोगों का कहना है। पीपल वो वृक्ष है जो छाव तो देता ही है, बल्कि हार्ट अटैक जैसी बड़ी बिमारी को भी मात देने की ताकत भी रखता है। बहुत ही कम लोग इस पीपल के पत्तों के इन फायदों को जानते है। रोजाना पीपल के पत्तों का पानी पीने से हार्ट अटैक का खतरा टल जाता है। जो लोग हार्ट अटैक के रिस्क के साथ जीते है, उन्हें इस पीपल के घरेलु उपायों को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। जिन लोगों को हार्ट अटैक आ चूका है, वे कुछ दिन छोड़कर इस उपाय का इस्तेमाल करें। रोजाना एक पीपल की पत्तियां लिजिए व उसे एक गिलास पानी में पकाइए, जब पानी एक तिहाई रह जाए तो उसे ठंडा करके पी लीजिए। ध्यान रहे की पत्ती के ऊपर का भाग काटकर अलग रख दें। पीपल के इन पत्तों को लेने का भी अलग तरीका होता है। इस दवा को दिन में तीन बार पिया जाता है।15 दिन इस काढ़े को पीने से दिल के दौरे का खतरा कम हो जाता है। पीपल का पत्ता दिल को अद्भुद ताकत देता है। इस काढ़े तो दिन में तीन बार लेना चाहिए, एक सवेरे नाश्ता करने के बाद 8 बजे, एक 11 बजे और एक दिन में 2 बजे। पीपल के पत्तों का उपचार करते वक्त तली हुई चीजें, मांस, मच्छी, शराब, धूम्रपान , नमक खाना बंद कर दें। इस उपचार को करते वक्त मैथी दाना,बथुआ,आंवला, अनार, पपीता,सेब का मुरब्बा, मौसंबी, रात में भिगोए काले चने, किशमिश, गुग्गुल, दही, छाछ का सेवन. सेब का मुरब्बा, मौसंबी, रात में भिगोए काले चने, किशमिश, गुग्गुल, दही, छाछ। ध्यान रहे उपचार करते समय हरे, कोमल और विकसित पत्ते ही लीजिए, भूलकर भी पीपल के गुलाबी कोपलों को न लें।

शहद के उपयोग से बारिश में नहीं आएंगी बीमारियां

हम सब जानते हैं कि बारिश के मौसम में बड़ी जल्दी- जल्दी बीमार पड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और ज़रा सा बारिश में भीग जाने की वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं।अगर आयुर्वेद की मानें तो, हमारे पास शहद है जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरी होती है। शहद का एक चम्मच रोजाना सेवन करने से हमारा शरीर बारिश की तमाम बीमारियों से बचा रह सकता है। आइये जानते हैं शहद हमारी रक्षा कैसे करेगी...

वायरल फीवर और सर्दी-खांसी से लड़े

शहद में एंटीऑक्सीडेंट और रोगाणुरोधी गुण होते हैं, जो खांसी और गले की समस्या में राहत प्रदान करती है। वे लोग जिन्हें रेसपिरेट्री ट्रैक इंफेक्शन होता है उनके लिए भी शहद लाभकारी है। 1 कप गरम पानी में 1 चम्मच नींबू का जूस और 1 चम्मच शहद मिक्स के धीरे धीरे सेवन करना चाहिए।

पेट के संक्रमण से राहत दिलाए

शहद में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो एक अच्छा बैक्टीरिया होता है। यह पेट संक्रमण और फूड प्वाइजनिंग से आपकी रक्षा करेगा इसलिए रोजाना 1 चम्मच शहद का सेवन करना न भूलें।

इम्यूनिटी बढ़ाए

शहद में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच अदरक का रस और नींबू का रस मिला कर गरम पानी के साथ पिएं। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी।

बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचाए

शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं। यह बैक्टीरिया और जर्म से लड़ने में मदद करती है। बारिश की वजह से कॉलरा और डायरिया ना हो जाए इसलिए आपको शहद का सेवन जरुर करना चाहिए।

रेसिपी

पापड़ पनीर फ्रिटर्स

सामग्री

1 कप चूरा किया हुआ पनीर, नमक स्वादअनुसार, 1 टेबल-स्पून कसा हुआ लहसुन, 1 टी-स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टी-स्पून टमेटो कैचप, 1/3 कप मैदा, 3/4 कप क्रश किए हुए पापड़, **तलने के लिए:** तेल , **परोसने के लिए:** टमेटो कैचप

विधि

पनीर को प्लेट में रखकर अच्छी तरह गूंथ लें। नमक, लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, टमेटो कैचप डालकर अच्छी तरह मिला लें। मिश्रण को 9 बराबर भाग में बांट लें और प्रत्येक भाग को 50 मिमी (2) लंबे गोल आकार में रोल कर लें। एक तरफ रख दें। मैदा और 1/2 कप पानी को बाउल में अच्छी तरह मिला लें। प्रत्येक रोल को मैदा-पानी के पेस्ट में डुबोकर क्रश किए हुए पापड़ में लपेट लें और सभी तरफ सुनहरा और करारा होने तक तल लें। तेल सोखने वाले कागज में निकालकर, टमेटो कैचप के साथ तुरंत परोसें।

मिक्स्ड वेजिटेबल सागु

सामग्री

सागु मसाला के लिए: 2 स्पून उड़द दाल, 2 से 3 हरी मिर्च , कटी हुई, 4 से 5 काली मिर्च, 2 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून ज़ीरा, 1/2 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 4 स्पून कसा नारियल। **अन्य सामग्री:** 1 स्पून घी/ नारियल का तेल/ अन्य तेल, 1 स्पून सरसों, 1 स्पून उड़द दाल, 1 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च , टुकड़ो में तोड़ी हुई, 1/2 टी-स्पून हींग, 7 से 8 कड़ी पत्ता, 1/4 कप बारिक कटा हुआ प्याज़, 2 कप कटी हुई मिली-जुली सब्जियां, 1/2 टी-स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वादअनुसार, 1 स्पून सागु मसाला पाउडर , 1 चक्र फूल और 1 तेजपत्ता

विधि

सागु मसाला पाउडर के लिए: एक छोटा पैन गरम करें और लगातार हिलाते हुए, उड़द दाल के सुनहरा होने तक, मध्यम आंच पर सूखा भुन लें। एक तरफ रख दें। ठंडा करने के बाद, शेष बची हुई सामग्री डालकर मिक्सर में पीसकर मुलायम पाउडर बना लें। एक तरफ रख दें। **आगे बढ़ने की विधि:** कढ़ाई में घी/तेल गरम करें और सरसों डालें। जब बीज चटकने लगे, उड़द दाल, लाल मिर्च, हींग और कड़ी पत्ता डालकर अच्छी तरह मिला लें और लगातार हिलाते हुए, दाल के सुनहरा होने तक मध्यम आंच पर भुन लें। प्याज़ डालकर मध्यम आंच पर उनके पार्दर्शी होने तक लगातार हिलाते हुए भुन लें। मिली-जुली सब्जियां, हल्दी पाउडर, नमक और 11/4 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें और ढ़ककर, बीच में एक बार हिलाते हुए, 12 से 15 मिनट तक मध्यम आंच पर, सब्जियों के नरम होने तक पका लें। सागु मसाला पाउडर डालकर हल्के हाथों मिला लें और 5 मिनट तक धीमी आंच पर उबाल लें। चक्र फूल और तेज़पत्ता से सजाकर गरमा गरम परोसें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 550 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।भाजपा नेता अभिजीत दास (बाबी) की शिकायत पर दक्षिण 24 परगना जिले के थानों में दर्ज इन मामलों में 300 करोड़ रुपये की कथित अवैध मिट्टी कटाई तथा चक्रवात अम्फान के दौरान राहत सामग्री वितरण में 250 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।पहली एफआइआर कालीतला आशुती थाने में दर्ज कराई गई है। इसमें अभिषेक बनर्जी, उनके निजी सचिव सुमित राय, विष्णुपुर के तृणमूल विधायक दिलीप मंडल समेत कुल 23 लोगों को आरोपित बनाया गया है। शिकायत के अनुसार, वर्ष 2017 से एक संगठित गिरोह के जरिए लगभग 163 बीघा कृषि भूमि की उपजाऊ मिट्टी अवैध रूप से काटकर विभिन्न व्यावसायिक कार्यों के लिए बेची गई। आरोप है कि यह कारोबार 2022 और 2023 में और तेज हुआ।

नीट-यूजी विवादः जुलाई में होगी अगली सुनवाई

नईदिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने तीन मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) को कथित पेपर लीक की घटनाओं के कारण रद्द कर दिया था। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है और 21 जून को पुनः परीक्षा निर्धारित है।बुधवार को, मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष नीट-यूजी 2026 की पुनः परीक्षा आयोजित करने के फैसले को रद्द करने की मांग वाली एक याचिका सुनवाई के लिए आई। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यह याचिका जुलाई में जस्टिस नरसिम्हा की पीठ द्वारा सुनी जाएगी, जब शीर्ष अदालत अपने नियमित कामकाज के लिए फिर से खुलेगी। उल्लेखनीय है कि जस्टिस नरसिम्हा की पीठ पहले से ही नीट-यूजी से संबंधित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।नई याचिका में केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से भविष्य की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए सुरक्षित प्रौद्योगिकी-संचालित डिजिटल परीक्षा और मूल्यांकन तंत्र लागू करने का निर्देश दिया।

ओपी राजभर का बड़ा दावा सपा में हो सकती है बड़ी टूट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जल्द ही एक बहुत बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि अब अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि जब कोई बिकने के लिए तैयार होता है, तभी उसे खरीदा जाता है। राजभर ने सपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर सीधा निशाना साधते हुए दावा किया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक गुप्त पत्र भेजा है, जिसमें कुछ नाम देकर उन्हें अपने साथ ले जाने और खुद को सुरक्षित रखने की बात कही गई है। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि सीबीआई ने अवैध खनन मामले में उनका नाम दर्ज किया है।

मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस

नईदिल्ली। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के छह सांसदों ने मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया है। भाजपा सांसदों का आरोप है कि मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री के बारे में सदन में अपमानजनक और असम्मानजनक टिप्पणी की, जिससे सदन की गरिमा और संसदीय परंपराओं का उल्लंघन हुआ है। इसी आधार पर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल किया गया।राज्यसभा के सभापति ने जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजाः राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इस नोटिस पर संज्ञान लेते हुए इसे आगे की जांच और परीक्षण के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। समिति मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सभापति को सौंपेगी। अब विशेषाधिकार समिति यह तय करेगी।

विपक्ष के लिए राजनीतिक बोझ बन गए हैं राहुल गांधीः शहजाद

नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि अब न केवल जनता बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी दलों का भी उन पर भरोसा नहीं रहा है। भाजपा ने दावा किया कि डीएमके के मुखपत्र मुरासोली में प्रकाशित संपादकीय राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठ रहे सवालों को उजागर करता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी विपक्षी दलों के लिए राजनीतिक बोझ बन गए हैं। उनका कहना था कि डीएमके के मुखपत्र में प्रकाशित लेख में राहुल गांधी पर गठबंधन सहयोगियों को कमजोर करने और विपक्षी एकता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि डीएमके ने राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से अपरिपक्व बताया है। उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु में डीएमके, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), वाम दल, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) जैसे दल समय-समय पर राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं।

टूट गई उद्धव की सेना, 6 बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को सौंपी चिट्ठी

नईदिल्ली। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) में आखिरकार फिर से फूट पड़ गई है। पार्टी के छह सांसदों ने बुधवार को दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओमप्रकाश बिरला से मुलाकात की और एक पत्र सौंपकर बताया कि वे एक स्वतंत्र गुट बना रहे हैं। स्पीकर ने आखिरकार इस अलग गुट को मंजूरी दे दी है, जिससे ऑपरेशन टाइगर सफल हो गया है। ये सांसद 19 जून को - जो शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है - महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। अलग गुट बनाने वाले छह सांसदों में संजय जाधव (परभणी), भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी), संजय देशमुख (यवतमाल), नागेश पाटिल अष्टिकर (हिंगोली), ओमराजे निंबालकर (धाराशिव) और संजय पाटिल (मुंबई उत्तर-पूर्व) शामिल हैं। इसके साथ ही, शिंदे की शिवसेना के पास अब 13 सांसदों की ताकत हो जाएगी, जिससे वे एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएंगे।

ये सभी छह सांसद मंगलवार रात दिल्ली पहुंचे थे ताकि वे एकनाथ शिंदे के साथ बैठक कर सकें। यह बैठक शिंदे के बेटे और सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे के दिल्ली स्थित आवास पर हुई। मंत्री प्रताप सरनाइक और सांसदों के अलावा, इस बैठक में 16 लोगों की कानूनी सलाहकार टीम भी मौजूद थी। शिंदे ने बहुत सावधानी बरती है ताकि उन्हें अयोग्य न ठहराया जाए।

लोकसभा सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने राज्यसभा सांसद संजय राउत के साथ बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कानून के तहत, कोई गुट सिर्फ़ इसलिए किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास दो-तिहाई सांसदों का समर्थन है। अगर किसी गुट के पास ज़रूरी दो-तिहाई संख्या बल है, तो भी सिर्फ़ मूल पार्टी ही विलय कर सकती है। देसाई ने आगे कहा, यह फ़ैसला स्पीकर को करना होता है। इसलिए, अगर दो-तिहाई समर्थन का दावा करने वाला कोई गुट किसी दूसरी पार्टी में विलय करने के लिए आता है, तो नियमों के तहत उस गुट को मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि प्रावधानों के अनुसार केवल मूल पार्टी ही विलय कर सकती है। भले ही छह सांसद हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।

बागियों को संजय राउत ने ऑन कैमरा दी गाली

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने पार्टी में फूट की बढ़ती अटकलों के बीच बागी सांसदों पर तीखा हमला किया। उन्होंने उन पर धोखा देने का आरोप लगाया और उद्धव ठाकरे गुट के प्रति उनकी वफादारी पर सवाल उठाए। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, राउत ने उनसे अरविंद सावंत और अनिल देसाई की बातों पर ध्यान देने को कहा और राजाभाऊ वाजे की निष्ठा की तारीफ की। बताया जाता है कि पार्टी के नौ सांसदों में से ये तीन ही सांसद हैं जो उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अब आप बस सुनें और समझें कि अरविंद सावंत और अनिल देसाई क्या कह रहे हैं। हमें राजाभाऊ वाजे की निष्ठा और ईमानदारी को भी देखना चाहिए।

राउत ने पार्टी के प्रति वाजे की बार-बार जताई गई वफादारी का ज़िक्र करते हुए कहा कि जब से वे (राजाभाऊ वाजे) ट्रेन से उतरे हैं, तब से वे कह रहे हैं कि वे उद्धव ठाकरे सेना के साथ हैं। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि राजनीतिक पद अस्थायी होते हैं लेकिन संगठन के प्रति वफादारी स्थायी होती है, राउत ने कहा विधायक और सांसद के पद आते-जाते रहते हैं। आज हम कानून बनाने वाले हैं, कल नहीं रहेंगे। लेकिन इस समूह ने हमें जो कुछ भी दिया है, उसे हम भूल नहीं सकते। बालासाहेब ठाकरे ने हमें बच्चों की तरह पाला-पोसा, उद्धव ने हमें भाइयों की तरह प्यार किया। इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़कर जा रहे लोगों को गालियां देते हुए कहा, ये साले... जो जा रहे हैं। फिर उन्होंने मीडिया वालों से कहा कि वे उनकी गालियों को सेंसर न करें।

अपनी बात आगे बढ़ाते हुए राउत ने बागी नेताओं पर बेईमानी का आरोप लगाया और कहा, ये लोग गद्दार हैं। शिवसेना (यूबीटी) में संभावित फूट की अटकलों के बीच, लोकसभा सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने बुधवार को दिल्ली में पार्टी के साथी और राज्यसभा सांसद संजय राउत से उनके घर पर मुलाकात की। शिवसेना (यूबीटी) के नौ सांसदों में से उद्धव ठाकरे का समर्थन करने वाले तीन सांसदों - अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे - ने बाद में संजय राउत के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गंभीर आरोप लगाए। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया, मुझे एक अहम व्यक्ति का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि सांसदों को 50 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया है, जिसमें से 15 करोड़ रुपए एडवांस के तौर पर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में सांसदों को खरीदा जा रहा है।

शिवसेना यूबीटी ने जारी किया व्हिप

पार्टी के भविष्य को लेकर बढ़ती अटकलों और संभावित दलबदल की खबरों के बीच, शिवसेना (यूबीटी) ने अपने सभी सांसदों के लिए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने का व्हिप जारी किया है। बुधवार को सांसद अनिल देसाई ने पुष्टि की कि पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने संसदीय बैठक बुलाई है। व्हिप जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि सभी सांसदों को मौजूद रहना चाहिए। उन्होंने विलय के खिलाफ सुरक्षा की मांग करने वाले पत्र की खबरों पर भी बात की और समझाया, देखिए, यह हमारे संविधान में भी है और हर पार्टी किसी न किसी तरह की सुरक्षा चाहती है। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत द्वारा बागी माने जा रहे सांसदों के लिए कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने के बारे में देसाई ने कहा कि इन टिप्पणियों को किसी खास व्यक्ति के खिलाफ नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जो कुछ भी कहा गया, वे आम बोलचाल के शब्द हैं; इनका मकसद किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं था। जब कोई भावनात्मक रूप से संवेदनशील व्यक्ति, जिसने राजनीति और सार्वजनिक जीवन में 50 साल बिताए हों, कुछ कहता है, तो ऐसी बातें हो जाती हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि वे किसी खास व्यक्ति को संबोधित नहीं कर रहे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावंत ने कहा कि ये हालिया घटनाक्रम और कदम उद्धव ठाकरे या हमसे सलाह करके नहीं उठाए जा रहे हैं। हमें ये खबरें मीडिया रिपोर्टों से मिल रही हैं। हमारी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा है कि वे पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पार्टी किसी व्यक्ति या समूह के हितों के बजाय सामूहिक ढांचे के आधार पर काम करती है। उन्होंने यह भी बताया कि शिवसेना (क्कञ्ज) ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संवैधानिक प्रावधानों की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमने संविधान की सुरक्षा के संबंध में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भेजा है। भविष्य में कोई भी कदम संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही होना चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों पर लोकसभा स्पीकर लेंगे बड़ा फैसला?

19 जून को अभिषेक बनर्जी को बुलाया

नईदिल्ली। सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को 19 जून को बातचीत के लिए बुलाया है। यह बातचीत 20 बागी सांसदों और इस मामले पर उनके रुख के बारे में होगी। यह घटनाक्रम विधानसभा चुनावों के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों के बाद हुआ है। 14 जून को, 20 बागी विधायकों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और एक पत्र सौंपकर अपने गुट का त्रिपुरा-स्थित नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ऑफ़ इंडिया में विलय करने का अनुरोध किया। उन्होंने संसद के निचले सदन में बैठने के लिए अलग व्यवस्था की भी मांग की।

सूत्रों के मुताबिक, स्पीकर ओम बिरला 20 बागी सांसदों के मामले की समीक्षा कर रहे हैं और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। इससे पहले भी उन्हें समन भेजा गया था, लेकिन अभिषेक बनर्जी उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, लोकसभा स्पीकर के ऑफिस ने 15 जून को दोपहर 2ः00 बजे बनर्जी को मीटिंग के बारे में ईमेल भेजा था। उस समय बनर्जी से प्रवर्तन निदेशालय (श्वष्ठ) पूछताछ कर रहा था, और पूछताछ के दौरान उनके पास अपना मोबाइल फोन या पर्सनल ईमेल देखने की सुविधा नहीं थी।

स्पीकर के ऑफ़िस ने बनर्जी को उसी दिन शाम 4 बजे तक दिल्ली में मिलने के लिए दो घंटे का समय दिया। ईमेल भेजने के एक घंटे के भीतर ही, स्पीकर के ऑफ़िस ने तय अपॉइंटमेंट के बारे में बताने के लिए तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आज़ाद से संपर्क किया। इसके बाद कीर्ति आज़ाद ने

स्पीकर के ऑफ़िस जाकर बनर्जी के न आ पाने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि श्वष्ठ की चल रही पूछताछ के बीच बनर्जी सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। आज़ाद ने बाद की कोई तारीख और समय मांगा और दोहराया कि बनर्जी स्पीकर की कार्यवाही में पूरी तरह सहयोग करना चाहते हैं।

उम्मीद है कि स्पीकर बागी गुट के विलय के अनुरोध पर विचार करेंगे, जिससे तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक नया कानूनी और राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। जहाँ बागी अपने कदम को आधिकारिक मान्यता दिलाना चाहते हैं, वहीं पार्टी नेतृत्व ने अपने सदस्यों को बचाने और अनुरोध की वैधता को चुनौती देने के लिए कदम उठाए हैं। बागी गुट का तर्क है कि हृष्टक्क्कढ्ढ के साथ विलय करके उन्होंने संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है। दलबदल विरोधी कानून के तहत, विलय की अनुमति तब दी जाती है जब किसी विधायी पार्टी के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। बागियों का दावा है कि उनके 20 सांसद इस सीमा को पार करते हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

आयरलैंड को हराकर इंग्लैंड ने दर्ज की दूसरी जीत

लीड्स। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मेजबान इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आयरलैंड को चार विकेट से हरा दिया। पहले गेंदबाजों ने आयरलैंड को 20 ओवर में 118/9 पर रोक दिया, फिर कप्तान नैट साइवर-ब्रंट और हीदर नाइट की अहम साझेदारी की बदौलत लक्ष्य हासिल कर लिया। हालांकि जीत के बीच इंग्लैंड को अपनी कप्तान की फिटनेस को लेकर चिंता भी सताने लगी है।

119 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और टीम ने शुरुआती तीन विकेट जल्दी गंवा दिए। इसके बाद नैट साइवर-ब्रंट और हीदर नाइट ने पारी संभाली और 64 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। नैट 37 गेंदों में 48 रन बनाकर खेल रही थीं, लेकिन 16वें ओवर में उनकी पुरानी पिंडली (काफ) की चोट फिर उभर आई। इसके चलते उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा और मैच अधिकारियों ने उन्हें रिटायर्ड आउट घोषित किया। वह अपने अर्धशतक से सिर्फ दो रन दूर रह गईं। मैच के बाद नैट ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगली बार वह उन दो रनों का इंतजार जरूर करेंगी। मैच के बाद हीदर नाइट ने बताया कि नैट को उसी काफ में हल्का खिंचाव महसूस हुआ, जिसमें पहले भी चोट लगी थी। उन्होंने कहा, उन्हें एहतियात के तौर पर मैदान से बाहर भेजा गया। अगले कुछ दिनों में उनकी जांच होगी और उम्मीद है कि वह जल्द फिट हो जाएंगी। इंग्लैंड का अगला मुकाबला 20 जून को स्कॉटलैंड से है। नैट की फिटनेस को देखते हुए इस मैच में उनका खेलना फिलहाल तय नहीं माना जा रहा है। यदि वह उपलब्ध नहीं होती हैं तो चार्ली डीन टीम की कप्तानी संभाल सकती हैं। हालांकि इंग्लैंड चाहेगा कि 24 जून को वेस्टइंडीज के खिलाफ अहम मुकाबले तक उनकी कप्तान पूरी तरह फिट हो जाएं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 347 अंक बढ़ा निफ्टी 24,085 पर बंद

नईदिल्ली। शेयर बाजार में आज लगातार चौथे दिन तेजी आई है। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद और कच्चे तेल की कीमत में गिरावट से शेयर बाजार उछला है। बीएसई सेंसेक्स 347.14 अंक की तेजी के साथ 77,155.62 पर पहुंच गया। जबकि निफ्टी 96.55 अंक ऊपर 24,085.70 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयर तेजी के साथ खुले। टेक महिंद्रा में सबसे ज्यादा तेजी रही। इसके अलावा इन्फोसिस, इंडिगो, ट्रेंट, टीसीएस, सन फार्मा, एचसीएल टेक और आईसीआईसीआई बैंक में भी उल्लेखनीय तेजी रही। दूसरी ओर, बजाज फाइनेंस, अडानी पोर्ट्स, रिलायंस, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, एनटीपीसी, कोटक बैंक, मारुति, पावरग्रिड ओर आईटीसी में गिरावट रही। ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी मिडकैप में 0.20 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप में 0.77 फीसदी तेजी आई।

मई में रत्न एवं आभूषण निर्यात 2.49 प्रतिशत घटा

मुंबई। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने कहा है कि सोने की ऊंची कीमतों और आपूर्ति में दिक्कतों के कारण मई में भारत का रत्न एवं आभूषण निर्यात सालाना आधार पर 2.49 प्रतिशत घटकर 204.79 करोड़ डॉलर (19,573.96 करोड़ रुपए) रह गया। जीजेईपीसी के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल इसी अवधि में निर्यात 17,896.16 करोड़ रुपए था। सोने के आभूषणों का कुल निर्यात मई में 14.75 प्रतिशत घटकर 75 करोड़ 84.4 लाख डॉलर (7,247.76 करोड़ रुपए) रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 88 करोड़ 96.3 लाख डॉलर (7,582.07 करोड़ रुपए) था। जीजेईपीसी ने बयान में कहा कि इस गिरावट की मुख्य वजह सादे सोने के आभूषण के निर्यात में भारी कमी थी, जो मई में 14.75 प्रतिशत घटकर 75 करोड़ 84.4 लाख डॉलर का रह गया।

वित्तवर्ष 26 में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत रिकॉर्ड स्तर पर

नई दिल्ली। भारत ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। सरकार ने बुधवार को जानकारी दी कि पिछले वित्त वर्ष (2025-26) में देश का सालाना रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अगर पिछले वर्ष यानी वित्त वर्ष 2024-25 से तुलना करें, तो इसमें 15.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उस समय यह आंकड़ा 1.54 लाख करोड़ रुपये था। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2020-21 के मुकाबले रक्षा उत्पादन में 110 प्रतिशत का उछाल आया है। उस समय उत्पादन केवल 84,643 करोड़ रुपये था। अगर हम वर्ष 2013-14 की बात करें, तो तब रक्षा उत्पादन 43,746 करोड़ रुपये था। इस तरह पिछले कुछ वर्षों में यह लगभग चार गुना बढ़ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरणादायी नेतृत्व को दिया है।

जापान का निर्यात मई में 17 प्रतिशत बढ़ा

तोक्या। जापान ने विद्युत मशीनरी के आयात में तेज वृद्धि से मई में चार महीने में पहली बार व्यापार घाटा दर्ज किया। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, जापान का निर्यात मई में सालाना आधार पर 17 प्रतिशत बढ़कर 9.51 लाख करोड़ येन (59.4 अरब अमेरिकी डॉलर) हो गया। आयात 12.5 प्रतिशत बढ़कर 9.89 लाख करोड़ येन (61.8 अरब अमेरिकी डॉलर) रहा। इससे 378.6 अरब येन (2.4 अरब अमेरिकी डॉलर) का व्यापार घाटा हुआ। ईरान में युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य में अवरोध से तेल और गैस के आयात में सालाना आधार पर 1.8 प्रतिशत की कमी आई। कंप्यूटर चिप और अन्य घटकों की मजबूत मांग के कारण विद्युत मशीनरी के आयात में 31.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अमेरिका-ईरान युद्ध खत्म?, अब बढ़ेगी आर्थिक रफ्तार

डॉ जयंती लाल भण्डारी

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के समझौते और पश्चिम एशिया में शांति की नई शुरुआत से कच्चे तेल के दाम में गिरावट वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सुकूनदायक है। इस युद्ध के खत्म होने और होर्मुज स्ट्रेट के खुलने से भारत सीधे तौर पर ऊर्जा संकट से राहत, महंगाई में कमी और निर्यात में वृद्धि से लाभान्वित होगा।

साथ ही वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती से खड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था अब तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में वैश्विक विकास दर घटकर 2.5 प्रतिशत रह जाएगी, वहीं भारत 6.6 प्रतिशत विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

वस्तुतः वैश्विक आर्थिक झटकों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचा, डिजिटल विकास, जीएसटी-आयकर सुधार, परमाणु ऊर्जा, व्यापार समझौते, सेवा क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग विकास से बेहतर स्थिति में है। सरकार तेजी से रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ संरचनात्मक सुधारों को गति देते हुए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है।

हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि की है। यह वित्त वर्ष 2024-25 की 7.1 प्रतिशत की विकास दर के मुकाबले बेहतर है। स्पष्ट है कि देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी बनी हुई है, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही है।

इसमें शक नहीं कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने से भारत की आर्थिक संभावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन चालू वित्त वर्ष

2026-27 में पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत के सामने भी आर्थिक चुनौतियां दिख रही हैं, इसलिए भारत को अर्थव्यवस्था को गति देने के नए उपाय भी सुनिश्चित करने होंगे।

सरकार को 'ईज ऑफ लिविंग' (जीवन को आसान बनाने) और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (कारोबार को सुगम बनाने) में सुधार के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ मौजूदा आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए विचार-मंथन किया।

इसके तहत लोगों के जीवन स्तर की बेहतरी, आपूर्ति श्रृंखलाओं के व्यवधान से निपटने, आर्थिक सुधारों को गति देने, उद्योग-व्यापार सुगमता जैसे कदमों से विकास दर बढ़ाने और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना सुनिश्चित किया गया।

निस्संदेह चालू वित्त वर्ष 2026-27 में जहां अर्थव्यवस्था के समक्ष अल-नीनो, कमजोर मानसून और सूखे की आशंका, महंगाई, ऊर्जा संकट, मांग में कमी तथा सख्त वित्तीय स्थितियों जैसी चुनौतियां हैं, वहीं दूसरी ओर तेजी से बढ़ते व्यापार समझौते, देश में लागू नए श्रम कानून और चालू वित्त वर्ष के दूरदर्शी बजट जैसे महत्वपूर्ण कारक देश की विकास दर को लगभग सात प्रतिशत के स्तर तक पहुंचाने के संकेत भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से पश्चिम एशिया में शांति से भारत के व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत आगामी 10 महीनों में नौ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) लागू करेगा। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार समझौता भी आगामी माह जुलाई के मध्य तक संभावित है। इससे देश निर्यात, विनिर्माण और निवेश का वैश्विक केंद्र बनने की राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में एक जून को भारत और ओमान के बीच वृहद आर्थिक एवं साझेदारी समझौता (सीईपीए) लागू हो गया है। इससे आगामी पांच वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 20 अरब डॉलर के पार पहुंचने का अनुमान है। खास बात यह है कि यह समझौता दक्षिण एशिया, खाड़ी क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका को जोड़ने वाला एक रणनीतिक आर्थिक गलियारा स्थापित करेगा। इससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत एफटीए की डगर पर तेजी से बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद को दी 603 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

सुशासन और पारदर्शिता राज्य सरकार की प्राथमिकता

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गरियाबंद जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित विशाल लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में जिलेवासियों को 603 करोड़ 46 लाख 32 हजार रुपये की लागत वाले 76 विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने 86 करोड़ 75 लाख 52 हजार रुपये की लागत से पूर्ण हुए 46 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 516 करोड़ 70 लाख 80 हजार रुपये की लागत से प्रारंभ होने वाले 30 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों से जिले में सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युत एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी तथा विकास को नई गति प्राप्त होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों एवं गरीब परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और सुशासन के माध्यम से योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 757 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिलों में राहत दी जा रही है, जिससे लाखों परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली मुक्त योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को बिजली खर्च से राहत मिलने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है।मुख्यमंत्री ने किसानों के हितों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में कृषि सहकारी साख समितियों के नए केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे किसानों को ऋण, खाद, बीज एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने का आह्वान करते हुए नैनो यूरिया के उपयोग पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया के उपयोग से उत्पादन लागत कम होती है, भूमि की उर्वरता बनी रहती है तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन और पारदर्शिता राज्य सरकार की प्राथमिकता है। आम जनता की समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 प्रारंभ की गई है। उन्होंने नागरिकों से इस सुविधा का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व मंच पर नई पहचान स्थापित कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही हैं।

अवैध स्क्रैप और प्रयुक्त बैटरियों के कारोबार पर सख्ती

पर्यावरण मंडल ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने राज्य में अवैध रूप से स्क्रैप एवं प्रयुक्त बैटरियों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) तथा व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंडल ने सभी व्यापारियों, कबाड़ संचालकों, स्क्रैप डीलरों, परिवहनकर्ताओं तथा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े हितधारकों को निर्देशित किया है कि वे अपना संचालन केवल बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 एवं अन्य प्रचलित वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही करें।

मंडल के संज्ञान में आया है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में बिना आवश्यक पंजीयन, प्राधिकार एवं वैध दस्तावेजों के प्रयुक्त एवं स्क्रैप बैटरियों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन तथा क्रय-विक्रय किया जा रहा है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की गतिविधियां पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं तथा पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन हैं। मंडल ने बताया कि बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के तहत प्रयुक्त एवं अपशिष्ट बैटरियों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन तथा व्यापार केवल विधिवत पंजीकृत एवं अधिकृत संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है। अपशिष्ट बैटरियों के परिवहन के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन तथा आवश्यक दस्तावेजों का संधारण अनिवार्य है। इसके साथ ही खरीद-बिक्री संबंधी अभिलेख एवं अन्य आवश्यक रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखना आवश्यक है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि खुले स्थानों पर अपशिष्ट बैटरियों का भंडारण, अनधिकृत संग्रहण, पर्यावरणीय मानकों के विपरीत संचालन अथवा अवैध व्यापार दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में राज्यभर में विशेष निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा।

खेलो इंडिया सेंटर की बेटी ने बढ़ाया प्रदेश का मान

रायपुर। राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें बेहतर मंच उपलब्ध कराने के प्रयास लगातार सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में जिला सूरजपुर के खेलो इंडिया सेंटर हराटिकरा की एक प्रतिभावान बालिका खिलाड़ी का चयन आवासीय खेल अकादमी रायपुर के लिए हुआ है। यह उपलब्धि न केवल सूरजपुर जिले बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।

ग्रामीण अंचल से निकलकर अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण के बल पर बालिका खिलाड़ी ने यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उसके चयन से यह साबित हुआ है कि उचित मार्गदर्शन, नियमित प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर प्रदेश की बेटियां किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं।इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने बालिका खिलाड़ी को फुटबॉल भेंट कर सम्मानित किया तथा उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि जिले की बेटियां खेल जगत में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और अपनी उपलब्धियों से अन्य बच्चों को भी प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने खिलाड़ी को निरंतर मेहनत, अनुशासन और लगन के साथ आगे बढ़ते हुए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।उल्लेखनीय है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित खेलो इंडिया सेंटरों के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं और युवा खिलाड़ी राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी पहचान बना रहे हैं।बालिका खिलाड़ी के चयन से जिले में हर्ष का माहौल है।

परमिट लेकर बस न चलाने वालों पर होगी कार्रवाई

रायपुर। परिवहन विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक में सचिव एवं परिवहन आयुक्त श्री एस प्रकाश ने कई कड़े निर्देश जारी किए। बैठक में ऋझ्रह्र/ष्ठझ्रह्र प्रवर्तन अमला, बस संचालक संघ और वाहन डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल हुए। आरटीओ/डीटीओ अब मुख्यालय छोड़ नहीं सकेंगे, सभी क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने पदस्थापना मुख्यालय में रहकर ही काम करने के निर्देश दिए गए। बैठक मेंअतिरिक्त परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर भी मौजूद थे।

जिलावार बकाया राजस्व की समीक्षा की गई। सचिव एवं परिवहन आयुक्त ने सभी ऋझ्रह्र/ष्ठझ्रह्र को वाहनों पर बकाया कर वसूलने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही जांच चौकियों और फ्लाइंग स्क्वॉड को बकायादार वाहनों की लिस्ट दी जाएगी।

बस स्टैंडों पर बसों की रोजाना मॉनिटरिंग होगी। बस आपरेटरों के द्वारा समय सारिणी तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परमिट लेकर भी बस न चलाने वाले संचालकों के परमिट निरस्त होंगे, ताकि नए आवेदकों को मौका मिले। बिना उपयोग खड़ी निजी बसों की जांच होगी।

राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक

रायपुर। राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा से आज यूनिसेफ इंडिया के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने नीति भवन नवा रायपुर में सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूनिसेफ इंडिया की फील्ड सेवा प्रमुख सोलेदाद हेरेरो ने किया। इस अवसर पर यूनिसेफ छत्तीसगढ़ फील्ड कार्यालय की प्रमुख सीमा कुमार एवं सामाजिक नीति प्रमुख डॉ. बाल परितोष दाश भी उपस्थित रहे। बैठक में विकसित छत्तीसगढ़ प्रगति फ्रेमवर्क, बाल कल्याण सूचकांक, बच्चों के लिए सार्वजनिक वित्त, सामुदायिक जागरूकता एवं सामाजिक व्यवहार परिवर्तन और बस्तर अंजोर कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा हुई। विकसित छत्तीसगढ़ - जहाँ बच्चे हैं विकास की नींव बैठक में राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष

मिश्रा ने स्पष्ट किया कि विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना में बच्चे केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि राज्य के विकास की आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य के प्रत्येक बच्चे को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और संरक्षण सुनिश्चित नहीं होता, तब तक विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य अधूरा है। विकसित छत्तीसगढ़ सामाजिक नीति सहयोग इकाई, नीति और जमीन के बीच सेतु राज्य नीति आयोग एवं यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से स्थापित विकसित छत्तीसगढ़ सामाजिक नीति सहयोग इकाई राज्य में साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत पहल है। यह इकाई विकसित छत्तीसगढ़ प्रगति फ्रेमवर्क, बाल कल्याण सूचकांक, बच्चों के लिए बजट विश्लेषण और सामाजिक संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य के विभागों को निरंतर तकनीकी सहयोग प्रदान करती है। बैठक में इस इकाई के कार्यों की सराहना की गई और इसे और अधिक सशक्त बनाने पर सहमति व्यक्त की गई।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

सरकार के संरक्षण में रेत माफिया बेलगामः दीपक बैज

रायपुर। पूरे प्रदेश में अब रेत का व्यापार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में गैंगवार का कारण बन चुका है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पूरे प्रदेश में रेत के लिए खून-खराबा मचा हुआ है। कोरिया जिले में बेहद ही डरावनी घटना घटी, एक भाजपा नेता ने दूसरे भाजपा के नेता उसके भाई और उसके साथी को

फॉर्च्यूनर गाड़ी में बंद करके पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया और दो लोगों की मृत्यु हो गयी और कुछ घायल लोगों को बड़े शहर में रेफर कर दिया गया है। सरकार के संरक्षण में रेत माफिया बेलगाम हो चुका है। भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री सीधी रेत के कारोबार में लिप्त है, उनके संरक्षण में अपराधी आतंक मचा रहे है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पूरे प्रदेश में रेत का खूनी खेल चल रहा है, सत्ता के संरक्षण में चल रहा है।बमुश्किल एक पखवाड़ा पहले जांजगीर-चांपा के जैजेपुर में घर में घुसकर के दो भाईयों को गोली मार दी जाती है। कुछ दिनों पहले बलरामपुर में रेत माफिया ने पुलिस कांस्टेबल पर ट्रैक्टर चढ़ा कर हत्या कर दिया।राजनांदगांव में रेत माफिया ने गोली बारी किया। गरियाबंद में रेत माफिया ने खनिज इंस्पेक्टर और माइनिंग अधिकारियों को दौड़ा-दौड़ा कर मारा।

शराब की ओवर रेटिंग की जांच कब होगी: शुक्ला

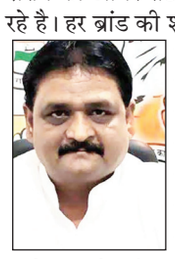

रायपुर। भाजपा सरकार बताये शराब के ओवर रेटिंग की जांच कब होगी। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में शराब धड़ल्ले से ओवर रेट में बेची जा रही है। इस पूरे खेल को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। शराब की ओवर रेंटिग सरकार में बैठे हुये लोग करा रहे है। हर ब्रांड की शराब में 60 से 80 रू. तक प्रति

बोतल वसूला जा रहा था। शराब के काऊंटर में बैठे लोग दावा कर रहे है कि शराब का पैसा ऊपर तक जा रहा था। यह मामला मीडिया मे आया और जनता ने विरोध किया तब जाकर कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करने की कार्यवाही की गयी। सरकार इस मामले की जांच की ईडी से कब करायेगी यह सुनियोजित घोटाला है। इसमें पूरी सरकार शामिल है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूरे प्रदेश में संगठित शराब घोटाला चल रहा। हजारो करोड़ रूपये वसूली हो रही है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी तब पता चलेगा कितने बड़े-बड़े लोग शामिल है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि भाजपा के सरकार में शराब घोटाला हुआ है ईडी, सीबीआई जांच करने से क्यों घबरा रही है? छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार नकली मिलावटी और अवैध शराब को बिकवा रही है। रायगढ़ में नकली शराब की बाटलिंग हो रही थी।

गर्मी में बच्चों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ः ठाकुर

रायपुर। गर्मी के चलते स्कूलों में बच्चों की तबियत बिगड़ने के लिए शिक्षा मंत्री को दोषी ठहराते हुये प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की 16 जून को स्कूल खोलने की जिद्द छोटे-छोटे मासूम बच्चों पर भारी पड़ रही है। बच्चे एवं पालक मजबूरी एवं दबाव में बच्चों को स्कूल भेजे। स्कूल

के पहले दिन ही प्रार्थना में बच्चों की तबियत बिगड़ने लगी। शिक्षक भी परेशान है। प्रदेश में पालक एवं कांग्रेस ने गर्मी को देखते हुए 1 जुलाई से स्कूल खोलने की मांग की थी, लेकिन एयरकंडीशन दफ्तर में बैठकर शिक्षा मंत्री को गर्मी की तपिश का एहसास नहीं हुआ। 16 जून को स्कूल खोलकर बच्चों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया। स्कूलों में न पंखा है, न कूलर है, न पानी की पीने की व्यवस्था है। पुस्तक, स्कूल ड्रेस भी नहीं पहुँचा है, ऐसे में स्कूल खोलने की क्या हड़बड़ी थी? प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि शिक्षा मंत्री को पालकों एवं बच्चों की मांग को सुनना चाहिये। स्कूल को 1 जुलाई तक स्थगित करना चाहिये। बच्चों को ऑनलाईन पढ़ाई करवाना चाहिए। कोविड कॉल में लंबे समय तक स्कूल बंद रहा, उस दौरान ऑनलाईन पढ़ाई हो रही थी।

प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं सरकार लापरवाह बनी हुईः वंदना

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल हो गयी है। बलरामपुर जंगल में गैंगरेप, भाई को बंधक बनाकर युवती से तीन तीन लोगों ने दरिंदगी की, पूरे प्रदेश में कानून

व्यवस्था बदहाल, हत्या, लूट, डकैती, चाकूबाजी, गैंगवार हो रहे हैं, खाकी और कानून का डर अपराधियों में खत्म हो गया है सुशासन है या जंगलराज? प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि प्रदेश में थम ही नहीं रहा अपराध का सिलसिला, कानून व्यवस्था फेल हो चुका है। पेंड्रा के कोटमी बाजार में सराफा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिछले 24 घंटों के भीतर ही राजधानी रायपुर के कुशालपुर क्षेत्र में गैंगवार हुआ। राजधानी रायपुर के ही गंज थाना क्षेत्र में सरेआम चाकूबाजी हुई, एक युवक की हत्या हो गई, उनसे जेवरात लूट लिए गए। बिन्द्रानवागढ़ के देवभोग में महिला समेत परिवार के चार सदस्यों पर धारदार ब्लेड से हमला कर दिया, महिला की गर्दन पकड़ कर ब्लेड चला दिया गया जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, मौके पर मौजूद उनके दोनों बेटे और पति गंभीर रूप से घायल हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद 1 दर्जन से अधिक लोगों की गोली मारकर हत्या हुई।

किसानों को डीजल उपलब्ध कराने में नाकाम सरकारः मिश्रा

रायपुर। आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने छत्तीसगढ़ के किसानों की सरकार द्वारा अनदेखी पर कहा है कि राज्य की भाजपा सरकार किसानों को भूखा मारने पर तुली हुई है। आगामी ख़रीफ फसल के लिए

अब डीजल के संकट से किसान जूझ रहा है। लंबे समय से डीजल नहीं मिलने के कारण खेती-किसानी के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है , मंत्री विधायक कार्यक्रमों में व्यस्त हैं? किसानी का 30 दिन का समय होता है यदि किसान को डीजल नहीं मिलेगा तो क्या कमाएगा। अभी सिर्फ 2000 रुपये का डीजल दे रहें हैं , लेकिन उतने डीजल तो खेत में 1 घंटे में खर्च हो जाता है,हर रोज किसान डीजल के लिए लाइन लगा रहें हैं। छत्तीसगढ़ का किसान सरकार से बहुत ज्यादा नाराज है। ज्ञात हो कि कल ही कांकेर में नाराज किसानों ने नेशनल हाइवे 30 को घंटो जाम कर बड़ा प्रदर्शन किया था। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी नाराज किसान प्रदर्शन करने मजबूर हो रहें हैं?उन्होंने कहा कि एक तरफ डीजल का संकट है तो दूसरी तरफ जहां पिछले खरीफ सीजन में भी खाद के संकट से छत्तीसगढ़ के किसान परेशान रहे।

केंद्रीय उपलब्धियों पर आधारित भव्य प्रदर्शनी का मंत्री केदार कश्यप ने किया उद्घाटन

टाउनहॉल में मोदी सरकार के 12 वर्ष की विशेष प्रदर्शनी

रायपुर। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी जिला रायपुर द्वारा टाउन हॉल, कलेक्ट्रेट परिसर, रायपुर में केंद्र सरकार की उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकसित भारत के संकल्प पर आधारित भव्य जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर केंद्र सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किए गए ऐतिहासिक कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की।

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता के कारण आज भारत विश्व पटल पर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सेमीकंडक्टर मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा उत्पादन एवं तकनीकी नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से करोड़ों नागरिकों को 5 लाख रुपये तक की नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है तथा गरीबों के लिए आवास, पेयजल, शिक्षा, कृषि एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं।

भाजपा जिला रायपुर के जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और राष्ट्र निर्माण के स्वर्णिम अध्याय रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। यह प्रदर्शनी तीन दिनों तक आमजन के लिए खुली रहेगी। प्रदर्शनी के अवलोकन हेतु भारतीय जनता पार्टी के मंडल, मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता निर्धारित तिथि एवं समयानुसार अपने-अपने क्षेत्रों के नागरिकों के साथ प्रदर्शनी स्थल पहुंचेंगे। उन्होंने रायपुर जिले के नागरिकों से भी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं ऐतिहासिक उपलब्धियों पर आधारित इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने का आग्रह किया।उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय प्रदर्शनी के सफल संचालन एवं समन्वय हेतु भाजपा रायपुर जिला उपाध्यक्ष अकबर अली को प्रदर्शनी प्रभारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसका मानव संसाधन : उद्योग मंत्री

रायपुर। वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन आज रायपुर में डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय (बिलासपुर) एवं आइसेक्ट इंडिया ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित दो दिवसीय समर्थ भारत कॉन्क्लेव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री देवांगन ने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसका मानव संसाधन होती है। भारत के पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है, लेकिन चुनौती है उन्हें आज के दौर के अनुसार हुनरमंद बनाना। श्री देवांगन ने कहा कि आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां परिर्वतन ही एक मात्र स्थिर चीज है और इस दौर में भारत को एक महा शक्ति बनाने का सबसे बड़ा सारथी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस । विकसित भारत के लिए ए.आई. संचालित कौशल विकास वित्तीय समावेशन और

सामाजिक उद्यम विषय पर आईसेक्ट द्वारा इसका आयोजन किया गया।

केबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि जब हम साल 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की बात करते हैं तो ए.आई. केवल एक तकनीक नहीं बल्कि वह इंजन है जो हमारे कौशल, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज को नई दिशा और रफतार देगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तब तक अधूरा है जब तक विकास की रोशनी देश के आखरी कोने में बैठे व्यक्ति तक न पहुंचे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.